



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 113]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20, 1980/ज्येष्ठ 30, 1902

No. 113]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 1980/JYAISTHA 30, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(प्राधिकार कार्य विभाग)

बजट अनुभाग

बजट 1980-81

वित्त मंत्री का भाषण

नई दिल्ली, 18 जून, 1980

पत्र सं० वि०सं० (बी ई ए) यू०ओ०सं० का० 15(1)-जी (डी)/80

(भाग क)

महोदय,

मैं वर्ष 1980-81 का नियमित बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित
हुआ हूँ।

2. इस वर्ष मार्च में अंतरिम बजट प्रस्तुत करने समय मैंने यह
बताया था कि हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की हालत कितनी ख़न्ता है
और उसे ठीक करने के लिए राष्ट्र को कितना भारी काम करना होगा।
पिछले सप्ताह सदन में प्रस्तुत "प्राथमिक समीक्षा" से मेरे उन बिचारों
की पुष्टि होती है, जो मैंने संक्षेप में मार्च के महीने में व्यक्त किए थे।
"प्राथमिक समीक्षा" में भारतीय अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान दशा और उसकी
समस्याओं तथा समाधानार्थों का विस्तृत ग्योरा दिया गया है, इसलिए मैं
यहाँ उसके कुछ प्रमुख पहलुओं पर ही प्रकाश डालूँगा ताकि सदन को
यह मालूम हो सके कि इस सरकार के सामने जो प्राथमिक समस्याएँ हैं

वे कितनी गंभीर हैं, उन्हें सुलझाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार-
वाई की है और आगे कौन-कौन से उपाय करने की ज़रूरत है, और
इन उपायों में से कुछ एक के बारे में मैं अपने इस भाषण में आगे बताऊँगा।

3. भारतीय अर्थ-व्यवस्था की सबसे अधिक महत्वपूर्ण और चिन्ताजनक
बात यह है कि 1979-80 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में लगभग 3 प्रतिशत
की गिरावट आई। यह गिरावट कृषि उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत
की और औद्योगिक उत्पादन में लगभग 1 प्रतिशत की कमी होने के कारण
हुई। कृषि उत्पादन में कमी इसलिए आई क्योंकि देश के बहुत बड़े
भागों में भयानक सूखा पड़ा। औद्योगिक उत्पादन में कमी होने का मुख्य
कारण यह था कि आधारभूत ढाँचे की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई
थी।

4. प्राथमिक निधि की जो सबसे अधिक गंभीर कठिनाईएँ रही उनमें
से एक कूटि बिजली, कोयला और रेल के उत्पादन से संबंधित थी।
इसमें कोई सन्देह नहीं कि सूखे के कारण पन-बिजली के उत्पादन में
2.2 प्रतिशत की कमी आई। लेकिन जो मुख्य बात हमारे सामने उभर
कर आती है वह यह है कि पिछले तीन वर्षों में तापीय बिजली के
उत्पादन की क्षमता में पर्याप्त बढ़ोतरी होने पर भी उसके उत्पादन में
बृद्धि करके बिजली की बड़ी हुई माँग को पूरा नहीं किया जा सका।
कोयले की अमूर्त पूर्ति और घटिया क्वालिटी, मशीनों आदि का घटिया
रख-रखाव, उत्सर्क की खराबों जिनके कारण पूर्व-योजना के अनुसार
तथा अत्यन्त भी बिजलीबन्दी की अवधियाँ बढ़ानी पड़ी और निरूप-
प्रबन्ध—ये सब ऐसी बातें थी जिनके कारण तापीय बिजली की क्षमता
का उपयोग घटकर 45 प्रतिशत तक ही रह गया।

5. कोयले की भी यही कहानी है। भारी पूंजी निवेश के बावजूद 1979-80 में कोयले और बिजली का उत्पादन ठीक 10.6 करोड़ मेट्रिक टन हुआ जो चार वर्ष पहले प्राप्त स्तर से थोड़ा-सा ही अधिक था। कोयले के उत्पादन में जो कमी हुई उसका कारण यह था कि कामादर घाटी निगम के कार्य-निष्पादन का स्तर अच्छा नहीं रहा और बिहार तथा बंगाल के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं रही। इसके अलावा, रेलवे के यातायात की कठिनाइयों के कारण कोयला प्रमाण मात्रा में राष्ट्रीय बिजलीघरों तक नहीं पहुँचाया जा सका।

6. वर्ष 1979-80 के दौरान प्रारम्भिक टन भार के रूप में रेलवे के राजस्व उपार्जक यातायात में 1978-79 में प्राप्त स्तर से 3.3 प्रतिशत की कमी रही। प्रारम्भिक टन भार के रूप में राजस्व उपार्जक यातायात में रेलवे ने 1976-77 में सर्वोच्च स्तर प्राप्त किया था और तब से उसमें बराबर कमी होती जा रही है। बिजली, कोयला और रेलवे—इन तीनों क्षेत्रों में जो कठिनाइयाँ रही उन्होंने परस्पर एक-दूसरे को बढ़ावा दिया और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की गंभीर क्षति पहुँचाई।

7. आधारभूत ढांचे की इन गंभीर कठिनाइयों के कारण इस्पात, सीमेंट बिजली-बिजल मशीनें, एल्यूमिनियम और अन्य अत्यंत धातुओं तथा सूती वस्त्रों जैसी प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन में कमी आना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। चीनी के उत्पादन में भी 28 प्रतिशत की कमी हुई। उद्योग के क्षेत्र में क्षमता के उपयोग में सामान्य रूप से गिरावट आई।

8. ऐसी स्थिति में जब कि समग्र पूँति में एकदम कमी आई, कीमतों में तेजी से वृद्धि हो गई। राजकोषीय वर्ष 1979-80 में कीमतें 20 प्रतिशत बढ़ीं। चाँदी, गेहूँ, खाँडगारी, नैलहन और खाद्य तेलों जैसी कुछ वस्तुओं की कीमतों में खासतौर से बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। उत्पादन के निम्नस्तर के कारण बहुत सी विनिर्मित और मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी होने का रुख बना रहा। कच्चे तेल और तेल उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होने के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण अर्थ-व्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव बढ़े और कोयले तथा इस्पात जैसी चीजों को प्रशामित कीमतों में बेर से लिए गए समायोजनों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। इसके कारण स्वाभाविक रूप से मटेरिवाजी के आसार बढ़ गए और पिछले वर्षों के दौरान मुद्रा उपलब्धि में अत्यधिक विस्तार किए जाने से मुद्रा प्रणाली में तकरों का बाहुल्य हो जाने के कारण कीमतों की स्थिति और भी गंभीर हो गई।

9. इन सभी बातों के कारण जिस एक अल्प क्षेत्र में स्थिति बिगड़ी वह था भुगतान-शेष का क्षेत्र। यह सही है कि 1979-80 में हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार में कुल मिलाकर केवल 56 करोड़ रुपए की ही कमी हुई किन्तु भुगतान-शेष पर असर डालने वाली विभिन्न शक्तियों का रुख स्पष्टतः उलट गया। मूल्य के रूप में निर्यात की वृद्धि केवल 8 प्रतिशत के आसपास रही जिसका मतलब यह हुआ कि परिमाण के रूप में नायब ही कोई वृद्धि हुई हो क्योंकि 1979-80 में विश्व स्तर पर लगभग 10 प्रतिशत की दर से मुद्रास्फाति हुई। दूसरी ओर, आयातों में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण यह था कि तेल का बिल बढ़ गया था क्योंकि तेल और तेल उत्पादों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई थी और उसका उर्वरक जैसी वस्तुओं के आयात पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप 1979-80 में व्यापार का घाटा 1978-79 के घाटे की तुलना में दुगुना यानी 2232 करोड़ रुपए का था। इसकी वजह से चालू खाते में भी घाटा रहा। बाहर से भेजी जाने वाली रकमों की वृद्धि की दर भी, जिसके कारण अभी कुछ समय पहले व्यापार का घाटा अधिशेष में बदल गया था, 1979-80 में धीमी पड़ गई।

10. यह असंतोषजनक आर्थिक स्थिति काफी हद तक पिछली सरकार की नीतियों या मैं यों कहूँ कि नीतियों के अभाव के कारण उत्पन्न हुई। उदाहरणार्थ, चीनी के सम्बन्ध में दुर्लभ नीति के कारण गन्ने के क्षेत्र में कमी हुई और चीनी का उत्पादन भी घट गया और पिछले मौसमों

में हफ़ठे किए गए चीनी के बिजान भंडारों की उनसे बार-बार चीनी निकाल कर बरबाद कर दिया गया और बाद में इन निकालियों का फिर कायम नहीं रखा जा सका। यदि वे चीनी के मामले में अधिक उत्तर-दायित्वपूर्ण नीति का अनुसरण करते तो हमें घरेलू उद्योग के लिए बाहर से चीनी मांगने की अवांछनीय स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता।

11. जहाँ तक आधारभूत ढांचे का संबंध है, कोयला, परिवहन और बिजली के तीन क्षेत्रों में समन्वित नीति न होने के कारण कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा। नकदी बाहुल्य वाला अर्थ-व्यवस्था में जहाँ बजट में 2700 करोड़ रुपए का भारी घाटा हो और घटते हुए उत्पादन की स्थिति में आम उपभोग की वस्तुओं पर आपक का से कर लगाने की नीति हो तो कीमतों में उछाल आना स्वाभाविक ही है। अन्ततः, निर्यात संबन्धित पर पर्याप्त बच न दिए जाने के कारण भी अंततः हमारे भुगतान-शेष का रुख उलट गया।

12. अतः अब यह जरूरी हो गया है कि हालत को और ज्यादा बिगड़ने से रोकने के लिए और अर्थ-व्यवस्था को स्थिरता और विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए उपाय खोजे जाएँ। इस तथ्य से कि हमारी सरकार को जनता का विश्वास प्राप्त है और उसमें निर्णय लेने की क्षमता है, स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए, इसके अलावा यह भी सही है कि अब जब कि राज्यों के चुनावों में हमारी पार्टी को इतने उत्पाद के साथ विजयी बनाया गया है, केन्द्र और राज्यों के बीच बहुत अधिक सहयोग रहेगा। हमने पहले जो दूरदर्शिता दिखाई थी उसके कारण अब मई 1980 के अंत में भी हमारे पास 180 लाख मेट्रिक टन खाद्य का भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार 30 मई, 1980 को 4890 करोड़ रुपए का था। स्थिति को सुधारने के लिए इन संश्लेषण तत्वों का संयोजनपूर्वक उपयोग किया जाएगा। लेकिन सदन यह महसूस करेगा कि हमें जितनी गंभीर और जटिल समस्याएँ विरासत में मिली हैं उनको अच्छी से सुलझाना कोई आसान काम नहीं है। किन्तु ये समस्याएँ ऐसी हैं जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, इसलिए हम दृढ़संकल्प होकर और जनता के सभी वर्गों के सहयोग से इन्हें सुलझाने का प्रयत्न करेंगे।

13. अब से इस सरकार ने सच्चा संभाला है तब से इतने आर्थिक प्रणाली की कठिनाइयों को ठीक करने के लिए कई कदम उठाए हैं। चूंकि आधारभूत ढांचे की स्थिति में लाने के काम में किसी प्रकार की देरी बर्बाद नहीं की जा सकती थी इसलिए सरकार ने स्थिति पर बराबर नजर रखने के लिए सैरी अध्यक्षता में आधारभूत ढांचे के बारे में एक संविमंडलीय समिति गठित की। चूंकि बिजली की कमी उत्पादन की वृद्धि में बाधा डालती रही है इसलिए समिति ने बिजली संबंधी स्थिति को सुधारने की ओर बहुत ध्यान दिया है। समिति इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था चाहती है कि राष्ट्रीय बिजली के उत्पादन में कोयले की कमी बाधा न बने इसलिए उसने यह निर्णय किया कि राष्ट्रीय बिजलीघरों को कोयला पहुँचाने के लिए अधिक बैंगन उलब्ध करवाए जाएँ। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय बिजलीघरों को प्रतिदिन भेजे जाने वाले कोयले के बैगनों की संख्या मई 1980 में 3200 हो गई है जबकि जनवरी में यह 2900 थी।

14. रेल द्वारा कोयले की बुलाई की अनुपूर्ति करने के लिए तटवर्ती तोहहन फिर से चालू किया गया है और आशा है कि परिवर्ती और दक्षिणी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और वह प्रति मास एक लाख मेट्रिक टन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

15. कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कई कदमों के फलस्वरूप उसके उत्पादन में अप्रैल और मई 1979 की तुलना में, अप्रैल 1980 में 9.4 लाख मेट्रिक टन और मई 1980 में 10.4 लाख मेट्रिक टन की वृद्धि हुई है।

16. पत्तों की स्थिति में भी आवश्यकतानुसार सुधार हुआ है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में घाट पर लगने के लिए प्रतीक्षा करने वाले जहज़ों की संख्या मई 1980 तक घटकर बहुत कम हो गई है। पत्तों की स्थिति

में सुधार हुआ है जिसका सहो निदेशक यह तथ्य है कि अप्रैल 1980 से धीरे धीरे कलकत्ता आदि बड़े पत्तनों पर लगने वाला संकुलन अभिभार (क-जेशन सरजार्ज) हटा दिया गया है।

17. जून अक्टूबर 1979 से मई 1980 तक की अवधि में वर्षों काम हुई जिसमें कई राज्यों में सूखे की स्थिति बराबर बनी रहनी और 23 करोड़ लोग इसमें प्रभावित रहे, इसलिए वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभालते ही तुरंत विशाल पैमाने पर राहत कार्य शुरू कर दिए। इन राज्यों तथा दूसरे राज्यों को भी केन्द्रीय धन भेजे गए और सूखा राहत के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि विधित की गई। इस साथ से अधिक निराश्रितों को मुक्त भोजन दिया गया। इसके अलावा, "काम के बने भोजन" के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजाना लगभग 65 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। सरकार ने इस कार्यक्रम को नवम्बर 1980 के अंत तक चालू करने का निश्चय किया है। नाइट्रोजनी उर्वरकों समेत कृषि में काम प्रति बाली वस्तुओं (इनपुट) पर छोटे और सामान्य किसानों को एक फसल वाले सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, जहाँ रबी की कोई फसल नहीं उगाई जा सकती, इस समय जो अधिक सहायता दी जाती है वह भी मार्च, 1981 के अंत तक दी जाता रहेगा।

18. सूखे के प्रबन्ध का एक 12 सूत्री कार्यक्रम तैयार करके राज्यों के पास भेजा गया है। इस कार्यक्रम में यह बताया गया है कि मूलतः किस प्रकार सूखे की स्थिति का मुकाबला करें और इसके लिए क्या बुद्धिकोण अपनाएं। कृषि खेती के लिए बहुत से रीतों को काम में लाया जा रहा है और बोर किए गए कुएँ में से काफी अधिक प्रतिशत कुओं में सफरता मिली है। आशा है, इन कदमों से सूखा-प्रभावित राज्यों में पाने के पानी की उपलब्धता में स्थायी रूप से सुधार हो सकेगा।

19. पिछले कुछ महीनों के दौरान, सूखा आदि कई कारणों से पेट्रोलियम उत्पादों, खास तौर से डीजल की मांग बढ़ गई। यह समस्या धीरे धीरे जटिल हो गई जब जनवरी से अप्रैल के कच्चे तेल (क्रूड) पर आश्रित जारी तेल शोधक कारखानों (रिफाइनरी) से जिनके द्वारा सामान्यतः प्रतिमास लगभग 3,50,000 मेट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पाद तैयार किए जाते हैं, होने वाली पूर्ति (सप्लाय) लगभग पूरी तरह ठप्प हो गई। इस स्थिति का पूर्ण तरह से मुकाबला किया गया। सर्वप्रथम, जनवरी और अप्रैल 1980 के बीच डीजल और मिट्टी का तेल अधिकतम मात्रा में आयात किया गया अर्थात् 6.2 लाख मेट्रिक टन मिट्टी का तेल और 11 लाख लाख मेट्रिक टन डीजल बाहर से मंगाया गया जबकि जनवरी-अप्रैल 1979 में आयातित मिट्टी के तेल और डीजल की मात्रा क्रमशः 4.7 लाख और 4.8 लाख मेट्रिक टन थी। दूसरे सभी उपलब्ध साधनों के द्वारा इन वस्तुओं की आवाजाही से तेजी लाई गई। इसके फलस्वरूप 1979 के पदतुल्य महीनों की तुलना में इनकी पूर्ति के स्तर में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई और डीजल की कमी रहने से रबी के उत्पादन पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता वह नहीं पड़ा।

20. जहाँ तक कीमतों का संबंध है, सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया है। खास तौरों के मामले में सरकार ने पर्याप्त मात्रा में इनका आयात ही नहीं किया बल्कि यह भी व्यवस्था की है कि आयात किए गए इन तेलों का काफी बड़ा भाग सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो। उम्मीद है कि लगभग 3 लाख मेट्रिक टन आयातित तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सहकारी समितियों के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगा। चीनी के मामले में, सरकार ने अस्तव्यस्त हुई बोहरी कीमत प्रणाली को सक्रिय बना दिया है।

21. गरीबों से गरीब व्यक्ति के विकास के लिए हमारा नीति में जो जोर दिया गया है उसका अनुसूच बँकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि परिश्रमि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का काफी बड़ा भाग पुनर्जर्जावित किए जा रहे 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम

के लाभानुभोगियों को प्राप्त हो। अणुस्तरिय विकास की गतिविधियों और बैंकों के ऋण कार्यक्रमों के बीच की कड़ी को और मजबूत करने के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे इस वर्ष के अंत तक उन सभी अणु मुख्यालयों (ब्लॉक डेवेलपमेंट्स) में अपनी शाखाएँ खोलें जहाँ इस समय बैंक कार्यालय नहीं है।

22. सम्पत्ति सवस्य उस महत्वपूर्ण भूमिका से भली भाँति परिचित है जो हमारे नियतों ने हमारे विकास कार्यों में निभाई है। इसलिए कई वर्षों से सरकार नियत सवस्य को सभी प्रकार के सुविधाएँ और पूरा-पूरा प्रोत्साहन देने की कोशिश करती रही है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जो उत्तरोत्तर प्रतिस्पर्धात्मक बनता जा रहा है, नियत सवस्य के लिए निवेश बिल और ऋण का प्रबंध करना अधिकारिक जटिल होता जा रहा है। इसलिए एक ऐसी विशिष्ट संस्था की जरूरत है जो नियत ऋण के सभी पहलुओं के लिए एक केन्द्र बिन्दु बने और जो नियतक सम्पदा की आवश्यकताओं पर एकाग्र होकर ध्यान दे। तदनुसार सरकार ने हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वित्त व्यवस्था में सहायता देने के लिए एक नियत-आयात बैंक स्थापित करने का निश्चय किया है। हमें आशा है कि यह विशिष्ट संस्था हमारे नियत सवस्य कार्यों को बाँटित बढ़ावा देगी।

23. इस समय अर्थव्यवस्था के समान जो समस्याएँ हैं उनको देखते हुए जो काम किए जाने हैं, वे काफी स्पष्ट हैं। चूंकि अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी संभाव्यता बहुत अधिक है इसलिए हमारी नीति का मुख्य उद्देश्य कीमतों में स्थिरता लाना होगा। समग्र पूर्ति में वृद्धि करके और समग्र मांग में कुछ कमी करके ही इस कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए हमारा ह्रादा है कि हम आधारभूत ढाँचे के कार्य में सुधार करने के अपने प्रयत्नों को जारी रखें और जहाँ कहीं आवश्यक हो पूर्वी निवेश करके उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाएं। दूसरे, जोर इस बात पर दिया जाएगा कि विद्यमान क्षमता का अधिक कारगर ढंग से उपयोग किया जाए, क्षमता बढ़ाने के प्रयत्नों में कोई ढील न दी जाए, और इस्पात, सीमेंट, एन्थ्रैसिटीयम, तथा उर्वरक जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाई जाए। इसमें एक साथ उत्पादन और रोजगार बढ़ाया, आयात का जरूरत कम होगी और राजस्व का लाभ होगा।

24. मांग प्रबन्ध के संबंध में, हमें बैंक ऋण के विस्तार को उत्पादक और प्राथमिकता प्राप्त प्रयोजनों के साथ जोड़ने की नीति का अनुसरण करना होगा और सड़कें के लिए धनराशि का इस्तेमाल को रोकना होगा। हमें एक ऐसी व्याज दर नीति का भी अनुसरण करना होगा जो उत्पादक कार्यक्रमों को अति पहुँचाए बिना स्फीतिकारी दबावों को कम करने में सहायक सिद्ध हो। इसी के साथ हमें मुद्रापाँचों और जमाखानों के विकसित हो कि व्यक्तिगत हित के लिए वर्तमान कमियों का फायदा उठाना चाहते हैं, कठोर कार्रवाई करनी होगी। तस्करी को तस्करी और विदेशी मुद्रा छलमाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम तथा अन्य उपायों के जरिये रोकना होगा।

25. मुद्राप्रणाली में तर्दी का बहुत बाहुल्य हो गया है इसलिए बजट के घाटे को 1979-80 के स्तर से बहुत नीचे रखकर मुद्रा उपलब्धि की वृद्धि को दृढ़तम स्तर पर सीमित रखने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए एक ऐसी राजकोषीय नीति की जरूरत होगी जो व्यर्थ और अनावश्यक व्यय को कम करे, साधनों को अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में लगाए, मौजूदा कर प्रणाली की राजस्व उपार्जन की क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाए।

26. हमारे भुगतान-शेष की बिगड़ी हुई हालत को देखते हुए हमें निर्यात संवर्द्धन के कार्य पर पिछले तीन वर्षों की ध्वेषा कहीं ज्यादा जोर देना होगा। साथ ही, खाद्य तेलों, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, तेल और तेल उत्पाद जैसी वस्तुओं के मामले में देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए और अधिक सशक्त नीति के माध्यम से आयातों की वृद्धि को निम्नतम स्तर पर रखना होगा।

27. सरकार ऐसी नीतियों का भी अनुसरण करना चाहती है जिससे ग्रामीण-व्यवस्था में बचत और निवेश को बढ़ावा मिले । 1971 से, लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा औद्योगिक एकाईयों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से संबंधित करारों में एक संपरिवर्तनीयता खण्ड रखा जा रहा है । उद्योग क्षेत्र द्वारा बार-बार यह अभ्यावेदन दिया जाता रहा है कि संपरिवर्तनीयता खण्ड की कठोरताओं के कारण पूंजी निवेश में रुकावट आ रही है सरकार ने सावधानीपूर्वक इस मामले पर विचार किया है और यह निर्णय किया है कि करारों में संपरिवर्तनीयता खण्ड शामिल किए जाने के लिए नीति संबंधी मार्ग-निर्देशों को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाए:—

- (क) संपरिवर्तनीयता खण्ड के अतिरिक्त समावेश की शर्तें इस समय-विहित 50 लाख रुपए की बजाय, भविष्य में 1 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता के संबंध में हो लागू होंगी ।
- (ख) वित्तीय संस्थाओं को एतद्वशात् संपरिवर्तन संबंधी विकल्पाधिकार का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे कि वे किसी मौजूदा कंपनी को गेयर पूंजी के 40 प्रतिशत से अधिक शेयर न लें । किन्तु अणुओं की वापसी भ्रष्टाचार में बराबर चूक किए जाने के मामले में या सहायता प्राप्त कंपनी के कुप्रबंध के मामले में ग्रथका समाज के लिए आवश्यक सेवाओं या वस्तुओं का उत्पादन करने वाली किसी कंपनी की औद्योगिक इकाई के लगातार बंद रहने पर, वित्तीय संस्थाएं सरकार की सहमति से, अपने संपरिवर्तन संबंधी विकल्पाधिकार का प्रयोग इस प्रकार कर सकती हैं जिससे कि उनकी गेयर धारिता 51 प्रतिशत तक या उससे उपर जा सकती हो ।
- (ग) जूट, सूत, वस्त्र, सिमेंट, चीनी और कृतिपय इंजीनियरी उद्योगों के प्राधुनिकीकरण के लिए इस समय जो उधार ऋण योजनाएं चल रही हैं उनका अन्तर्गत फलहाल कोई संपरिवर्तनीयता खण्ड शामिल नहीं किया जा रहा है । यह छूट अब अन्य सभी प्रकार के उद्योगों के प्राधुनिकीकरण और क्षण एकाईयों के पुनरुद्धार के लिए वा जाने वाले सहायता के मामले में भी दी जा रही है ।

सरकार को आशा है कि इन नीति विषयक परिवर्तनों से मौजूदा ऋणों दूर हो जायेंगी और उद्योग के प्राधुनिकीकरण को और उससे नए पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा ।

1980-81 की आयोजना और बजट अनुमान

28. अधिक प्रबन्ध का तात्कालिक समस्याओं में व्यस्त रहते हुए भी हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए कि ग्रामीण-व्यवस्था के विकास की क्षमता का निर्माण मध्यम काल में ही करना जरूरी है । यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो अल्पकालिक कठिनाइयां बढ़ती ही चली जाएंगी । पुनर्गठित योजना आयोग उस समय नए कार्यक्रम और प्राथमिकताएं प्रस्तुत करेगा जब इस वर्ष के अंत तक आयोजना तैयार कर ली जाएगी । लेकिन इसी बीच वर्ष 1980-81 के लिए आयोजना तैयार कर ली गई है जिसे बाद में छठी आयोजना में समाविष्ट कर लिया जाएगा । आयोजना का मोटा उद्देश्य 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की अपेक्षाकृत ऊंची वृद्धि दर प्राप्त करना होगा ।

29. 1980-81 की वार्षिक आयोजना का उद्देश्य ग्रामीण-व्यवस्था को पुनरुज्जीवित करना और उसे पूर्ववत् स्वस्थ बनाना है तथा विकास और रोजगार के प्रबन्ध पैदा करने की गति को तेज करना है । हालांकि पिछली सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएं हमें स्वीकार्य नहीं हैं फिर भी हमने यह माना है कि पहले से चली आ रही परियोजनाओं के लिए पूरी-पूरी व्यवस्था की जाए । इस विचार से समायोजन क्षमता की परिधि में रहते हुए हमने आयोजनागत व्यवस्थाओं में परिवर्तन किए हैं और नये कार्यक्रमों के लिए इस प्रकार व्यवस्था की है ताकि आयोजना को वांछित दिशा दी जा सके ।

30. नए योजना आयोग ने आयोजनागत कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं की तुरंत समीक्षा की है । मुझे यह बताने हुए प्रसन्नता हो रही है जिस समीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र की 1980-81 की वार्षिक आयोजना के परिचय को बढ़ाकर 7340 करोड़ रुपए किया जा रहा है, इस प्रकार अन्तर्गम बजट में व्यवस्थित परिचय में 767 करोड़ रुपए की वृद्धि की जा रही है । और यदि पिछले वर्ष के मूल परिचय से इसकी तुलना की जाए तो यह उससे 14.5 प्रतिशत अधिक है । इसकी वित्त-व्यवस्था के लिए बजट में 5322 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है और 2018 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आन्तरिक और अन्य साधनों से जुटाए जा रहे हैं । राज्यों की आयोजनाओं, संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं और पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों की उप-आयोजनाओं के परिचय के लिए, अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक आयोजनाओं, उत्तर-पूर्वी परिषद् की योजनाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और वैसी विपत्तियों से केन्द्रीय सहायता देने के लिए 3094 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । उनके अपने साधनों सहित उनका आयोजना परिचय 7253 करोड़ रुपए का होगा जबकि 1979-80 में यह परिचय 6099 करोड़ रुपए का था । केन्द्र, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी परिषद् की योजनाओं प्रावि का समस्त आयोजना परिचय कुल मिलाकर 1980-81 में 14,593 करोड़ रुपए का होगा, जबकि 1979-80 में यह 12,511 करोड़ रुपए का था; इस प्रकार उसमें 16.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी ।

31. इस सरकार का यह पक्का विश्वास है कि अधिक विकास की गति को तभी तेज किया जा सकता है और इसके सुफलों का व्यापक रूप से बंटवारा तभी किया जा सकता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में विशेष वृद्धि की जाए । हमारी जनता के बहुसंख्यक लोगों के लिए तब तक विकास का कोई मन्त्र नहीं होगा जब तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोग संतोषजनक उत्पादक कार्य के जरिये अपनी जीविका नहीं कमा सकेंगे । इसलिए हमने नई आयोजना के एक अभिन्न अंग के रूप में एक विशाल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाने का निर्णय किया है जो एक ऐसी नीति पर आधारित है जिसका उद्देश्य स्वावलंबन के अवसरों और उपलब्ध स्थानीय साधनों के इष्टतम उपयोग में सामंजस्यस्थापित करता होगा । ऐसे कार्यक्रम से ग्रामीण ग्रामीण-व्यवस्था में फिर से प्राण फूटने और जन-जीवन के लिए अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं का विकास करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी ।

32. इस संबंध में "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम को भी, जिसे हमने 1977 में शुरू किया था एक महत्वपूर्ण भूमिका भूषा करनी है । लेकिन पिछले दो वर्षों में इस कार्यक्रम में कुछ बुनियादी कमजोरियां दिखाई दी हैं । बहुत से मामलों में, ऐसी परियोजनाओं की एक तालिका बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई जो न केवल स्थानीय जरूरतों को ही पूरा करेंगी बल्कि जो समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भी ठीक से समाविष्ट हो सकेंगी । आद्यान के वार्षिक आवंटन के लिए भी कोई पक्का संकेत नहीं दिया गया । इस प्रकार इस कार्यक्रम को वस्तुतः एक तथ्य आधार पर ही चलाया जा रहा था । राज्य सरकारों द्वारा उनको आर्बिट्ररी आद्यान की सहायता से चलाए जाने वाले निर्माण कार्यक्रम के नकदी अंश की वित्त-व्यवस्था के लिए भी कोई प्रबन्ध नहीं किए गए थे । इसका परिणाम यह हुआ कि वे ऐसे निर्माण कार्य हाथ में नहीं ले सके जिनसे टिकाऊ परिणामितियों का निर्माण होता और संबंध क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती ।

33. नए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में, राज्यों को आद्यान के रूप में ही नहीं बल्कि नकदी के रूप में भी सहायता मिलेगी जिससे वे ऐसे निर्माण कार्य हाथ में ले सकेंगे जो आस्तब में उत्पादक होंगे और स्थायी लाभ देंगे । सबन में जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं उनमें इस कार्यक्रम के लिए 1980-81 में 340 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । अनुमान है कि यदि यह कार्यक्रम ठीक तरह से कार्यान्वित किया गया तो इससे 85 से 90 करोड़ श्रमिक दिनों का अतिरिक्त रोजगार पैदा होगा । इस योजना के लिए की गई व्यवस्था का कुछ भाग सामाजिक बन्धन, जनाने की लकड़ी के वृक्षारोपण, ग्रामीण सामुदायिक आवास और जल-पूर्ति

तथा पोषाहार जैसे उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

34. आर्थिक विकास की प्रक्रिया तब तक अधूरी रहेगी जब तक कि हम विकास के लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक दशा का सुधार करना हमारी विकास नीति का प्रमुख तत्व होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए व्यापक विशेष संघटक आयोजनाएं तैयार करनी होंगी जिनका उद्देश्य प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में सभी सगन क्षेत्रों में परिस्वय निर्धारित करना हो। इन परिस्थितियों का उपयोग अनुसूचित जाति के परिवारों को अपने रहन-सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए संगत कौशल और आय पैदा करने वाली परिस्थितियाँ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इस प्रयोजन से राज्यों को 100 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था करके हम बजट में एक नई शुरुआत की गई है; यह राशि वित्तीय संस्थाओं सहित अन्य साधनों से और अधिक घनगणि प्राप्त करने के लिए प्रेरक तत्व का कार्य करेगी। इसके जगह प्राधिकारी अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने के एकीकृत कार्यक्रम के लिए आवश्यक सभी सामग्री को एक साथ व्यवस्था कर सकेंगे।

35. जनजातीय लोगों और जनजातीय उप-आयोजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के विकास के लिए 70 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है। 10,000 की आबादी वाले ऐसे कुछ और इलाकों का पता लगाया जाएगा जहाँ कम से कम 50 प्रतिशत निवासी जनजाति के हों और इस प्रकार अठारह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की लगभग 75 प्रतिशत जनजातीय आबादी को जनजातीय उप-आयोजना के अंतर्गत लाया जाएगा। जनजातीय परिवारों को लाभ पहुंचा सकने वाले कुछ चुने हुए कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जाएगा।

36. बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंग के रूप में, भूमिहीन और कमजोर वर्गों के लिए घर बनाने के वास्ते जमीन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से 1980-81 की वार्षिक आयोजना में लगभग 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत संभालित, भूमिहीन मजदूरों के लिए ग्रामीण आवास-एन्ड-मोपट्री निर्माण की योजना में घर बनाने के लिए जमीन की ही नहीं बल्कि शोपडिया बनाने के लिए सहायता देने की भी व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक आवास परियोजनाएं शामिल होंगी, इस व्यवस्था की अनुपूर्ति की जाएगी। उम्मीद है कि इस योजना के अंतर्गत लगभग 8 लाख भूमिहीन परिवारों का लाभ पहुंचेगा।

37. चूंकि भारत गांवों में रहता है और इसकी लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि से अपनी जीविका चलाती है, इसलिए देश की समृद्धि कृषि के आधुनिकीकरण पर निर्भर करती है। 1979-80 का वर्ष हम निष्कर्ष तथ्य की याद दिलाता कि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि का कार्यनिष्पादन कितना महत्वपूर्ण है। चालू वर्ष में कृषि और ग्रामीण विकास के आयोजना परिस्वय को 1979-80 के 1811 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2247 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इस राशि में केन्द्रीय आयोजना के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं शामिल हैं छोटे किसानों की विकास एजेंसी सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के लिए 158 करोड़ रुपए; अन्तर्देशीय और समुद्री मछली उत्पादन क्षमता के बेहतर उपयोग के लिए 32 करोड़ रुपए; भरपूर दूध II परियोजना के लिए 54 करोड़ रुपए; बेहतर बीजों, बेहतर मत्स्य-वैज्ञानिक प्रणालियों बेहतर जल प्रबंध और उर्वरकों तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं के बेहतर इस्तेमाल के जरिये कृषि की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उद्विष्ट कृषि अनुसंधान और शिक्षा की योजनाओं के लिए 59 करोड़ रुपए; और 120 लाख मेट्रिक टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेलहनो के उत्पादन की वृद्धि के लिए 10 करोड़ रुपए।

38. तेल और तेल उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के वर्तमान स्तरों ने अन्य ईंधनों के महत्व को उजागर कर दिया है। ऐसे एक ईंधन की व्यवस्था करने के लिए जंगल महत्वपूर्ण भूमिका भूदा कर सकते हैं। चूंकि भारत में लोगों ने ईंधन की खोज में जंगलों का बहुत तेजी से सफाया किया है, इसलिए यह आवश्यक है कि जंगलों के विकास में तत्कालीन आधार पर लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाए। गांवों में सामाजिक वनपालन से लोगों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं सा पूनी होंगी हों, साथ ही उनको अतिरिक्त रोजगार भी मिलेगा। ईंधन और चारापैदा करने के काम का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अंग बनाने का प्रस्ताव है और इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

39. उत्पादन में घट-बढ़ को दूर करने के लिए और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाते जाने के कार्य पर बराबर जोर देने रहना होगा। अतः 1980-81 में बाढ़ नियंत्रण सहित बड़े और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए परिस्वय को, पिछले वर्ष के 1258 करोड़ रुपए से बढ़ाकर, 1380 करोड़ रुपए किया जा रहा है। सिंचाई के कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए 266 करोड़ रुपए के परिस्वय की व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्था के अलावा, इसी प्रयोजन के लिए कृषि पुनर्विनिर्माण और विकास निगम से भी बड़े मात्रा में वित्तीय सहायता मिलेगी। इन सम्पूर्ण व्यय से, आशा है, 25 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का निर्माण होगा।

40. ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के स्तर को सुधारने के लिए स्वच्छ और निरापद पेय जल एक आवश्यक वस्तु है। 1980-81 की केन्द्रीय आयोजना में, 1979-80 के 80 करोड़ रुपए के मुकाबले में, 100 करोड़ रुपए के परिस्वय की व्यवस्था की गई है। राज्यों का आयोजनाओं में की गई व्यवस्थाओं को शामिल करने पर इन महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए कुल 294 करोड़ रुपए उपलब्ध होंगे। आशा की जाती है कि चालू वर्ष के अन्त तक, समस्याग्रस्त माने गए 35,000 अतिरिक्त गांवों के लिए सुरक्षित जलपूर्ति की व्यवस्था कर दी जाएगी। परिस्वय के एक अंश का उपयोग सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कूप खोद, करने के उद्देश्य से राज्यों को आवंटित के लिए किया जाएगा। नई जलपूर्ति योजनाएं हाथ में लेने के लिए और पहले से हाथ में ली गई योजनाओं को पूरा करने के लिए सूखा प्रभावित राज्यों को आधु वर्ष में लगभग 40 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है।

41. खादी, ग्राम और लघु उद्योगों के क्षेत्र में, कृषि के बाद, सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने की संभावित क्षमता है। इस क्षेत्र के लिए चालू वर्ष में 150 करोड़ रुपए का परिस्वय रखा गया है और इस वर्ष इस क्षेत्र में 146 करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन का अनुमान है। सबन को याद होगा कि इस संबंध में 20 सूचों आर्थिक कार्यक्रम में हाथ-करघा क्षेत्र के विकास पर खास तौर से जोर दिया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त के लिए, हम राष्ट्रीय स्तर पर एक हाथ करघा विकास निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव करने हैं ताकि हाथकरघा उद्योग के लिए एक साथ विपणन और विकास संबंधी सहायता की व्यवस्था की जा सके। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, जो अपने बढ़िया हाथकरघा कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, एक हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

42. बिजली के क्षेत्र के लिए की जाने वाली व्यवस्था में 11 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि कर दी गई है अर्थात् इस वर्ष, 1979-80 में की गई 2466 करोड़ रुपए की व्यवस्था के मुकाबले 2745 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। देश के विभिन्न भागों में उच्च तापीय बिजली घरों के काम में तेजी लाई जा रही है। वर्ष 1980-81 में गांवों में बिजली लगाने के कार्यक्रम के लिए कुल 285 करोड़ रुपए का परिस्वय रखा गया है। वर्ष 1980-81 में 4 लाख पम्पसेटों को बिजली देने और 25,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

43. इसी प्रकार, कोयले (लिगनाइट सहित) का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1980-81 में 473 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है जबकि पिछले वर्ष इस काम के लिए 364 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। इस रकम में नेबेली लिगनाइट निगम के लिए की गई 92 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है। इस व्यवस्था में से अधिकांश राशि दूसरी जगह परियोजना के लिए है जिसके अन्तर्गत प्रति वर्ष 45 लाख मैट्रिक टन कोयले का उत्पादन होगा और 620 मेगावाट की उत्पादन क्षमता का दूसरा तापीय बिजली घर लगाया जाएगा। चालू वर्ष में 1135 लाख मैट्रिक टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जबकि 1979-80 में वास्तविक उत्पादन 1060 लाख मैट्रिक टन का हुआ था।

44. तेल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण भुगतान शेष पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए तेल के हमारे अनेक साधनों का तत्काल विकास करने की आवश्यकता के बारे में दो मत नहीं हो सकते। पेट्रोलेियम क्षेत्र के लिए वर्ष 1980-81 की आयोजना में 837 करोड़ रुपए का परिचय रखा गया है जो पिछले वर्ष के परिचय से 215 करोड़ रुपए अधिक है। इस परिचय में से बजट में केवल 99 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह परिचय आम्बे हाई से विकास के तीसरे चरण की सुविधाओं को पूरा करने और चौथे चरण के संबंध में अग्रिम कार्रवाई करने के लिए है ताकि वार्षिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 120 लाख मैट्रिक टन किया जा सके। इसमें साउथ बेसिन गैस फील्ड के विकास और नई उर्वरक परियोजनाओं तक गैस पाइप लाइन बिछाने का खर्च भी शामिल है। पूर्वी क्षेत्र में हाइड्रो कार्बन मिलने की ऊँची संभावनाओं की देखते हुए उस क्षेत्र में तट पर अन्वेषणात्मक खुदाई (ड्रिलिंग) का काम तेज किया जाएगा।

45. वर्ष 1980-81 की केन्द्रीय आयोजना में रसायनों तथा उर्वरकों के परिचय को बढ़ाकर 319 करोड़ रुपए किया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र और ग्रामाम में गैस पर आधारित नए उर्वरक कारखानों के लिए समुचित व्यवस्था की जा सके। इसके अतिरिक्त, महकारी क्षेत्र की उर्वरक परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है।

46. चालू वर्ष की केन्द्रीय आयोजना में इस्पात क्षेत्र के लिए भी पिछले वर्ष के 600 करोड़ रुपए के परिचय की तुलना में 803 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस परिचय में बांकारा इस्पात कारखाने की वार्षिक क्षमता को 40 लाख मैट्रिक टन तक बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपए की और भिलाई इस्पात कारखाने के संबंध में ऐसे ही विस्तार के लिए 190 करोड़ रुपए की रकम शामिल है। सेलम परियोजना का काम अग्रेषित गति से चलता रहेगा जिसके लिए 57 करोड़ रुपए का परिचय रखा गया है। नए विशाखापत्तनम् इस्पात कारखाने के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था के साथ एक अग्रणी खासी शुद्धाण की जाएगी। चालू वर्ष के लिए वित्तीय योग्य इस्पात का लक्ष्य 87.6 लाख मैट्रिक टन रखा गया है जबकि 1979-80 में 72.2 लाख मैट्रिक टन के उत्पादन की आशा थी।

47. खान क्षेत्र के लिए 1980-81 में 130 करोड़ रुपए का परिचय रखा गया है। इस व्यवस्था में नई पूर्वी तटवर्ती ऐल्यूमीनियम परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपए, सर्वज्ञ खण्ड तांबा परियोजना के लिए 28 करोड़ रुपए तथा भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण और खनिज अन्वेषण निगम के कार्य-कलाप को तेज करने के लिए 19 करोड़ रुपए की रकम शामिल है।

48. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की चालू योजनाओं तथा हरिद्वार में बड़े आकार के टर्बो जनरेटरों के उत्पादन और तिरुची में बायलर निर्माण क्षमता के विस्तार के लिए 64 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

49. चूंकि अभी हाल में विकास कार्य में बाधा के रूप में पत्तनों पर भीड़-भाड़ की बड़ी चर्चा रही है इसलिए बड़े और छोटे पत्तनों का विकास करने के लिए 102 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन 1980-81 के बजट में इस प्रयोजन के लिए केवल 60 करोड़ रुपए की ही व्यवस्था की गई है क्योंकि शेष खर्च की व्यवस्था पत्तन न्यासों द्वारा

स्वयं अपने आन्तरिक साधनों से की जाएगी। कंटेनर यातायात की प्रत्या-शित वृद्धि से निपटने के लिए बम्बई, मद्रास और कोचीन में मशीनें टैरार्ड जा रही हैं। कोचीन पत्तन के समर्पित भिक्काम के लिए शुद्धाण की जा चुकी है।

50. डाक-तार विभाग के लिए 1980-81 का आयोजना परिचय 415 करोड़ रुपए रखा गया है। इस वर्ष 1.75 लाख लाइनों की अति-रिक्त स्विचिंग क्षमता, 1.7 डायरेक्ट एक्सचेंज लाइनों और ग्रन्थ सुविधाओं के लिए व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण, पिछड़े और पहाड़ी इलाकों में डाक घरों की संख्या बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। जनजातीय क्षेत्रों में तार और टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था करने के मतकों को और उदार बना दिया गया है ताकि 10 किलोमीटर के घेरे के अन्दर घाटे वाले 2500 की आबादी वाले गांवों के समूह को भी तार और टेलीफोन की सुविधाएं पहुँचाई जा सकें। स्विचिंग उपकरणों की निर्माण क्षमता के विस्तार के लिए भी व्यवस्था की गई है।

51. पिछले तीन वर्षों में परिवार नियोजन के काम को भारी धक्का पहुँचा है। यदि लोगों के रहन-सहन का परिचरितियों को सुधारना हमारा उद्देश्य है तो इस कार्यक्रम में फिर से नई जान डालना नई पंचवर्षीय आयोजना का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 1980-81 में 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। इसमें से 140 करोड़ रुपए परिवार कल्याण के लिए होंगे। परिवार कल्याण कार्यक्रम में लोगों की छोटे परिवार की बांछनीयता के बारे में शिक्षित करने और पर्याप्त स्तर पर आवश्यक तकनीकी सेवाओं की व्यवस्था करने पर बल दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने, संचारी रोगों का उन्मूलन करने तथा स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि में प्रयास किया जाएगा।

52. पैमठ करोड़ का जनसंख्या वाले गरीब समाज के विकास की समस्याएँ निश्चय ही बहुत बड़ी होंगी। एक उचित समय के अन्दर अन्तर इन समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्तियों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। सामान्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी विपणन काफी संख्या में है और पिछले तीन वर्षों में भारत में एक बहुत व्यापक संस्थागत आधारभूत ढांचा तैयार हो गया है। यद्यपि हमारी वैज्ञानिक संस्थाएँ विज्ञान के क्षेत्र के विस्तार में सहायक मिष्ट हो सकती हैं लेकिन उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में तो विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी ही काम आ सकती है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 1980-81 की केन्द्रीय आयोजना में 116 करोड़ रुपए का परिचय रखा गया है।

53. अब मैं कुछ उन परिवर्तनों का संक्षेप में उल्लेख करूँगा जो आयोजना भिन्न व्यय में किए गए हैं। रक्षा व्यय के लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह रकम अन्तर्गत बजट में की गई व्यवस्था से 300 करोड़ रुपए अधिक है। नियंत्रण के लिए और अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता का देखा हुआ निर्णय के लिए दो जाने वाला प्राथिक सहायता की राशि 330 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 355 करोड़ रुपए कर दी गई है।

54. अन्तर चलन संग्रहों में होने वाले प्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकारों के हिस्से के रूप में उन्हे दिए जाने वाले ऋणों की राशि अन्तरगत बजट के 650 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 715 करोड़ रुपए कर दी गई है। खर्चों में काम आने वाले बाली वस्तुओं के लिए राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋणों की रकम में भी 50 करोड़ रुपए की वृद्धि की जा रही है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आन्तरिक महंगाई भत्ता, परमाणु बिजलीघरों के लिए भारी पानी की खरीद आदि जैसी अनिवार्य बचतबद्धताओं को पूरा करने के लिए भी अति-रिक्त व्यवस्था करना जरूरी हो गया है। लेकिन उर्वरकों पर दो जाने वाली प्राथिक सहायता में कटौती कर दिए जाने से आयोजना-भिन्न व्यय की ये वृद्धियाँ कुछ हद तक प्रतिसंतुलित हो जाएँगी।

55. सविधान में सरकार द्वारा निशुल्क कानूनी सहायता देने की परिभाषिता की गई है ताकि आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण कमी तारिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न होना पड़े। कानूनी सहायता की संकल्पना के विधान में व्यापारिक गी० एन० भगवती की अध्यक्षता में स्थापित विधिक सहायता समिति द्वारा विचार किया गया है; इस समिति की दिनांक 31 अगस्त, 1977 की रिपोर्ट सभा के सम्मुख प्रस्तुत कर दी गई है। कई राज्य कानूनी सहायता संबंधी कार्यक्रम चलाते की दिशा में प्रयत्नशील हैं। इस संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के बाद इन योजनाओं का समन्वय करने और केन्द्र स्तर पर उपयुक्त योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। कानूनी सहायता संबंधी योजनाओं का मार्गदर्शन करने और उन्हें प्रमत्त में लाने के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा रहा है। वर्ष 1980-81 के बजट में इस प्रयोजन के लिए व्यवस्था की गई है।

56. उपर्युक्त तथा कुछ अन्य परिवर्तनों के प्रभाव को हिसाब में लेने के बाद अब कुल मिलाकर 13051 करोड़ रुपए के आयोजना भिन्न व्यय का अनुमान लगाया गया है जबकि अन्तरिम बजट में 12822 करोड़ रुपए का अनुमान था।

57. जहां तक चालू वर्ष की प्राप्ति का संबंध है कराधान के वर्तमान स्तरों के अनुसार निगम-कर से अन्तरिम बजट में दिखाई गई राशि की तुलना में 11 करोड़ रुपए की अधिक प्राप्ति का अनुमान है; यह वृद्धि मुख्य रूप से 1979-80 के संग्रह की वास्तविक प्रवृत्तियों पर आधारित है। वर्ष के दौरान आय और उत्पादन के अनुमानित स्तरों के संबंध में उपलब्ध सबसे हाल के आंकड़ों के आधार पर अन्तरिम बजट की तुलना में सीमा-शुल्कों से 40 करोड़ रुपए और संघ उत्पाद-शुल्कों से 108 करोड़ रुपए की अधिक प्राप्ति होने का अनुमान है। लेकिन हाल में सरकार द्वारा उधरकों पर से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क हटा लेने के निर्णय के परिणामस्वरूप उपर्युक्त अधिक प्राप्ति का बहुत कुछ धराबर हो जायेगी। करों में राशियों के हिस्से को हिसाब में लेने के बाद कराधान की वर्तमान दरों पर अब 8723 करोड़ रुपए का निवल कर राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है जबकि अन्तरिम बजट में 8725 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था।

58. सबसे हाल के उपलब्ध संकेतों के आधार पर 1980-81 में बापसी आय-प्रणियों की घटाने के बाद 1252 करोड़ रुपए की निवल विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है। यह रकम अन्तरिम बजट में दिखाई गई राशि से 36 करोड़ रुपए अधिक है। इसके अतिरिक्त 1980-81 में हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भास निधि से 540 करोड़ रुपए का ऋण मिलने की आशा है और बजट में इसके लिए इतनी रकम जमा खाने में माय की गई है।

59. प्रत्यक्ष बचत संग्रहों में हुई वृद्धि स्वागतयोग्य है। इन बचतों से अब 1980-81 में 1100 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है जबकि अन्तरिम बजट में 1000 करोड़ रुपए का अनुमान था। सो करोड़ रुपए की इस वृद्धि में से 65 करोड़ रुपए राशियों को उनके हिस्से के रूप में प्राप्त होंगे।

60. यह निश्चय किया गया है कि जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और भारतीय युनिट ट्रस्ट के निवेश योग्य साधनों का एक हिस्सा सरकार के विशेष जमा खानों में रखा जाए ताकि आयोजना की वित्त व्यवस्था के लिए जुटाए जाने वाले साधनों में वृद्धि हो। वर्ष 1980-81 के बजट में इन जमा राशियों के लेखे 100 करोड़ रुपए की प्राप्ति को हिसाब में लिया गया है।

61. अब हम सरकारी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना चाहते हैं तब हमारे लिए यह जरूरी है कि हम ऐसे निवेश को बनाए रखने के लिए साधन जुटाने की समस्या के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं, गैर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों जनता से जमा रकमों के रूप में धन लेकर साधन जुटाती हैं। सरकार यह सोचती है कि सरकारी

क्षेत्र की कंपनियां भी जिनके पास सक्षम व्यावसायिक प्रबंधक हैं ऐसे क्यों न करें। अब हमने सरकारी क्षेत्र के कुछ चुने हुए एकाकों को गैर-सरकारी कंपनियों की भांति लोगों से जमा की रकमें जुटाने की इजाजत देने का फैसला किया है। अब यह योजना चला पड़ेगी तब सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की बजट समर्थन पर निर्भरता कम हो जायेगी। लेकिन मैंने इस समय ऐसी किसी राशि की प्राप्ति के रूप में हिसाब में नहीं लिया है।

62. अन्य परिवर्तनों की तथा रेलों के यात्री किराये और माल भाड़े की दरों तथा डाक और तार की शुल्क दरों के परिवर्तनों के प्रभाव को हिसाब में लेने के बाद जिनकी वृद्धि में थोड़ा भाग चल कर करूंगा, 1980-81 में कुल मिलाकर 19827 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है, जबकि अन्तरिम बजट में 18980 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। कुल मिलाकर 21467 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। इस प्रकार करों की वर्तमान दरों के अनुसार 1640 करोड़ रुपए का बाटा रहेगा।

(भाग—क)

63. अब मैं प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र से संबंधित घपने प्रस्तावों की ओर आता हूँ। इन प्रस्तावों को तैयार करने में मैंने मोटे तौर पर कुछ बातों को ध्यान में रखा है जो ये हैं: प्रत्यक्ष करों की दरें ऐसी होनी चाहिए कि लोग स्वेच्छा से ही उनका पालन करें; हमारी पार्टियों के घोषणापत्र में दिए गए वचनों के अनुसरण में किसानों, कामगारों और मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ राहत दी जानी चाहिए, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बचतों और निवेश का स्तर उच्च करने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। साथ ही आय और धन को टुकड़ों में बांटकर कर से बच निकलने की जो कुछ तरीकें व्यापक रूप से प्रचलित हैं उनको रोकने के लिए एक समन्वित प्रयास किया जाना चाहिए।

64. हाल के वर्षों में, कीमती में हुई वृद्धि से जो लोग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं उनमें मध्यम वर्ग भी शामिल है। सम्मानित सदस्य जानते हैं कि छूट के वर्तमान स्तर पर संगठित क्षेत्र के कुशल कामगारों को भी इस समय कर देना पड़ता है। इस वर्ग के लोगों को कुछ राहत देने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वैयक्तिक आय पर आय कर की छूट सीमा को 10000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये कर दिया जाए। इसके परिणामस्वरूप होने वाली राजस्व की हानि को सहाय सीमाओं में रखने के उद्देश्य से आय के शून्य दर खण्ड को पूर्ववत् 8000 रुपये पर ही रखा जा रहा है। इसके फलस्वरूप जिन मामलों में कराधेय आय 12000 रुपये में ऊपर होगी उनमें अधिभार को छोड़कर आय-कर का भार मौजूदा स्तरों पर ही रहेगा तथापि जहां कराधेय आय छूट सीमा से मामूली-सी ज्यादा होगी उन मामलों में सीमान्त राहत दी जायेगी। इस प्रस्ताव से छः लाख से ज्यादा आय-करदाताओं को लाभ पहुंचेगा।

65. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि प्रत्यक्ष कर जांच समिति की सिफारिश पर 1974 में वैयक्तिक आय पर आय-कर की दरें कम कर दी गई थीं और इस प्रक्रिया को 1976 में एक कदम और आगे बढ़ाया गया था जब इन दरों को और कम कर दिया गया था। दरों में इस प्रकार कमी कर दिए जाने से यह आशा बहुत हद तक पूरी हो गई थी कि इससे कर संबंधी कानूनों का पहले से अधिक पालन होगा। दुर्भाग्य से इस दिशा में हो रही प्रगति जनता सरकार के शासन में उलट दी गई और आय-कर की दरें कई अवस्थाओं में बढ़ा दी गईं। मेरे विचार से इस स्थिति को ठीक किया जाना चाहिए। धन: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियम-भिन्न सभी श्रेणियों के करदाताओं के मामलों में वैयक्तिक आय पर अधिभार की दर को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए। इससे न केवल कर की अधिकतम सीमागत दर 72 प्रतिशत से बढ़कर 66 प्रतिशत हो जायेगी अपितु आय के सभी खण्डों के करदाताओं को लाभ पहुंचेगा।

66. पन्चम्यामियों की कीमतों में प्रायः तेजी से हुई वृद्धि को देखते हुए मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि चालू निर्धारण वर्ष में धन कर की छूट सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया जाए किन्तु जिन मामलों में कराधेय धन इस सीमा से अधिक होगा उनमें कर-भार मौजूदा स्तरों पर ही रखा जाएगा लेकिन सीमान्त राहत पूर्ववत् दी जाती रहेगी।

67. सरकार आशा करती है कि इन रियायतों से हमारे अधिकांश करदाताओं को अपने आय और धन के बारे में सही-पहिली घोषणा करने के लिए आवश्यक प्रेरणा मिलेगी।

68. मैं कुछ ऐसी तरकीबों को भी निष्कल करना चाहता हूँ जो कर से बचने के लिए अधिकतर अपनाई जाती है।

69. जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, कर संबंधी कानूनों में हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर-निर्धारण एक अलग तरीके से किया जाता है जिनका उचित कर-दायित्व से बच निकलने के लिए बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आय-कर और धन-कर दोनों के लिए हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के आंशिक विभाजनों की मान्यता को वापस ले लिया जाए। पहली जनवरी 1979 को या उसके बाद किए गए आंशिक विभाजनों को कर के प्रयोजनों के लिए कोई मान्यता नहीं दी जाएगी और कर इस आधार पर लगा जाते रहेंगे कि मौजूदा हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब आगे भी संयुक्त बना रहेगा।

70. इस समय ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों पर, जिनके एक या अधिक सदस्यों की स्वतंत्र आय छूट-सीमा से अधिक है, उन वर्गों से आय-कर लगता है जो व्यक्तियों (इंडिविजुअल्स) के मामले में लगने वाली दरों से कुछ ऊंची है। कर-परिवर्जन (टैक्स एक्जेंशन) के प्रयोजनों के लिए हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के उपयोग को और सीमित करने के उद्देश्य से मैं ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के मामले में आय-कर को दोगुना बढ़ाता चाहता हूँ। 66 प्रतिशत की अधिकतम सीमान्त दर अब 50,000 रुपये से ऊपर के आय-खण्ड पर लागू होगी और कुछ निचले खण्डों को वरें भी कुछ ऊंची कर दी जाएगी। हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के कर-निर्धारण के बारे में ये दो परिवर्तन कर दिए जाने से मैं आशा करता हूँ कि आय को टुकड़ों में विभाजित करने और कर-दायित्व को कम करने के उद्देश्य मात्र से अनेक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब बना लेने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी।

71. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि सरकार ने कर-परिवर्जन की तरकीब के रूप में निजी वैयक्तिक न्यामों (डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट) के उपयोग को रोकने के लिए 1970 में कई उपाय किए थे। किन्तु अनुभव से मालूम हुआ है कि ये उपाय पूरी तरह प्रभावशालक नहीं रहे और ऐसे न्यामों का ब्राह्म को बोलेंदा समाज तक नहीं रोकना सफल। इस लिए मैं निजी न्यामों से संबंधित उपबन्धों को कड़ा करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस समय वैयक्तिक न्यामों के सम्बन्ध में उनकी आय पर 65 प्रतिशत और उनके धन पर 1.5 प्रतिशत की समान दर अथवा व्यष्टि के मामले में लागू होने वाली दर में से जो भी ऊंची हो उसी दर से लगता है। मेरे प्रस्ताव के अनुसार ऐसे न्यामों पर आय-कर अधिकतम सामान्य दर और धन-कर 3 प्रतिशत की समान दर अथवा व्यष्टि के मामले में लागू होने वाली समुचित दर में से जो भी ऊंची हो उसी दर से लगेगा। मैं निजी न्यामों के कराधान के संबंध में और कई उपबंध करने का भी प्रस्ताव करता हूँ जिनका उद्देश्य इन करों से बच निकलने के उन रास्ते को बंद कर देना है जो सरकार के ध्यान में आए हैं। ये सभी उपबंध चालू निर्धारण वर्ष से ही प्रभावी हो जाएंगे।

72. पूर्ण और धार्मिक न्यामों का उपयोग कभी-कभी निजी स्वाधों के लिए कारबार या उद्योग पर नियंत्रण प्राप्त करने अथवा नियंत्रण को कायम रखने के लिए किया जाता है। 1975 में हमने पूर्ण और धार्मिक न्यामों की धनराशियों के निवेश का एक पद्धति निर्धारित की थी जिसे करों में छूट प्राप्त करते रहने के लिए अपनाया जरूरी था। इन न्यामों को सभी शर्तों और शर्तों से इस नई निवेश-पद्धति को अपनाने की सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से और कानून में यह व्यवस्था की गई थी

कि नई पद्धति को 1 अप्रैल 1978 से पहले अपनाया जा सकता है। बाद में यह तारीख 1 अप्रैल, 1981 तक बढ़ा दी गई। इस प्रकार निवेश न्यामों की नई नीति के अनुसार अपने आप को हलाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यह समय-सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

73. हमारे कर संबंधी कानूनों का उद्देश्य हमेशा जीवन बीमा, भविष्य निधियों और अन्य ऐसे ही साधनों के जरिये दीर्घकालिक बचतों को बढ़ावा देना रहा है। दुर्भाग्य से पिछले वर्ष बचतों को प्रोत्साहन देने वाले उप-बन्धों की प्रभावशालकता बहुत कुंठित हो गई जब बचत के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में एक साथ भारी कमी कर दी गई थी। सम्मानित सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं इन बचत संबंधी प्रोत्साहनों को 1979 के बजट से पहले के स्तरों पर फिर ला देने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रकार कर-बताना अनेक बचतों के पहले पांच हजार रुपये पर 100 प्रतिशत कटौती, अगले 5 हजार रुपये पर 50 प्रतिशत कटौती और शेष राशि पर 40 प्रतिशत कटौती के हकदार होंगे।

74. गृहस्थों के क्षेत्र में बचत को बढ़ावा देने के एक और उपाय के रूप में मैं आय-करदाताओं को एक विकल्प देने का प्रस्ताव करता हूँ जिसके अंतर्गत वे अपने प्रतिवार्षिक निवेश खातों में जमा पानी धनराशियों को वेब तारीखों के बाद भी जमा रख सकेंगे; इसके लिए उन्हें उन जमा राशियों पर लगने वाली मौजूदा दरों पर व्याज भित्ति रहेगा। इसके अलावा, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि मान्यता-राश भविष्य निधियों में जमा की गयी राशियों पर व्याज के संबंध में दो जाने वाली कर-छूट को उदार बना दिया जाए। इस समय ऐसी धन-राशियों पर उपर्युक्त व्याज की रकम पर वहां तक आय-कर नहीं लगता जहां तक कि वह रकम कर्मचारी की वेतन आय के एक तिहाई भाग से ज्यादा नहीं होती। मैं इस अधिकतम सीमा को हटा देने का प्रस्ताव करता हूँ।

75. उद्योग में नए पूंजी-निवेश को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ ही यह भी देखना होगा कि राजकोषीय प्रणाली से पूंजी-प्रधान तकनीकों के पक्ष में अनुचित झुकाव न हो जाए। इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नए औद्योगिक उपक्रमों, जहाजों और होटलों के संबंध में आगे भी कर-प्रवकाश रहे, मगर कुछ संशोधित रूप में। मेरे प्रस्ताव के अंतर्गत नए औद्योगिक उपक्रमों, जहाजों या अनुमोदित होटलों के संबंध में कर-प्रवकाश इन श्रौतों से हुई आय का एक त्रिनिदिष्ट प्रतिशतता के संबंध में ही उपलब्ध होगा। कंपनियों के मामले में इन श्रौतों से हुए लाभों का 25 प्रतिशत भाग मान वर्ष तक कर-मुक्त रहेगा। निगम-भित्त करदाताओं के मामले में कर-मुक्त लाभों की प्रतिशतता 20 प्रतिशत होगी। सरकारों समितियों के मामले में कर-प्रवकाश 10 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगा, जब कि कर्षादाताओं को अन्य श्रेणियों के मामले में यह अवकाश मान वर्ष तक रहेगा। यह रियायत उन सभी लघु औद्योगिक उपक्रमों के मामले में उपलब्ध होगी जो 31 मार्च, 1981 के बाद लेकिन 1 अप्रैल, 1985 से पहले, यानी नई पंचवर्षीय आयोजना को अवधि के अंत तक उत्पादन शुरू कर देंगे। अन्य औद्योगिक उपक्रमों के लिए रियायत तभी लागू होगी यदि वे आय-कर अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध वस्तुओं या चीजों का उत्पादन नहीं करते होंगे। यह रियायत उन अनुमोदित होटलों के मामले में भी उपलब्ध होगी जो उन अवधि में अपना काम करना शुरू कर देंगे और उन जहाजों को भी जो उन अवधि में अजित किए जाएंगे।

76. खामतौर से अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की कमी को देखते हुए नए निवेश को प्रोत्साहन देना जरूरी है। नए निवेश के लिए विशेष प्रेरणा देने के लिए मैं नई आयोजना अवधि में लगाई गई मशीनरी या संयंत्र पर उसकी स्थापना के वर्ष में एक प्रतिशत मूल्यह्रास की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ जिसकी राशि सामान्य मूल्यह्रास के 50 प्रतिशत के बराबर होगी। प्रस्ताविका अतिरिक्त मूल्यह्रास जहाजों, वायुयानों, सड़क परिवहन वाहनों, कार्यालय माधुनों (एम्पायस) या मशीनरी अथवा संयंत्र पर, जो कार्यालय परिषद अथवा निवास स्थान में लगे होंगे, उपलब्ध नहीं होगा।

77. वैज्ञानिक समुदाय में निराशा की भावना बहुत ज्यादा फैली हुई है। यह सरकार भी जानती है कि हमारे वैज्ञानिक और प्रयोगशाला विद् भारत के आर्थिक कार्यालय में कितना अधिक योगदान दे सकते हैं। सरकार अनुसंधान तथा विकास संबंधी कार्यकलापों को बढ़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए भी कृतसंकल्प है। इसलिए मैं किर्मा आन्तरिक अनुसंधान और विकास मुक्ति में किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए वास्तविक व्यय के 125 प्रतिशत के बराबर आनुपातिक कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ जहाँ यह व्यय एक ऐसे कार्यक्रम पर किया गया हो जो भारत की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो। इसके अलावा, मैं अनुमोदित प्रयोगशालाओं में प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय पर आनुपातिक कटौती से संबंधित मौजूदा उपबंध के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की आन्तरिक अनुसंधान और विकास सुविधाओं में किए गए इसी प्रकार के व्यय को भी उस उपबंध में शामिल किया जा सके। मुझे कोई संदेह नहीं कि सम्मानित सभ्य इन रियायतों का स्वागत करेंगे।

78. इस समय आय-करदाताओं की वित्तीय वर्ष के दौरान अपने खुद के कथनों या अनुमानों के आधार पर अग्रिम कर देना पड़ता है। जहाँ यह संभावना हो कि अनुमानित अग्रिम कर की राशि, वर्तमान आय पर लगने वाले कर से, अनुमान के 33 1/3 प्रतिशत से अधिक मात्रा में कम होगी वहाँ करदाताओं को अपने अनुमानों में वृद्धि कर देनी पड़ती है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कंपनियों के मामले में इस अग्रिम (माजिन) को 33 1/3 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया जाए। अन्य कर-दाताओं के लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस परिवर्तन से हम अग्रिम कर के रूप में देय कर का अधिक बड़ा हिस्सा वसूल कर सकेंगे और इस प्रकार इसका 1980-81 में सरकार की अर्थप्राय स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

79. कारबार और उद्योग-धंधों में अंधे और विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नियोजकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को लिए गए वेतन के 1 1/2 के बराबर आनुपातिक कटौती की व्यवस्था की जाए जहाँ यह वेतन एक वर्ष में बीस हजार रुपए से ज्यादा न हो। इसके अलावा मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि अंधे और विकलांग व्यक्तियों की कराधेय आय का हिस्सा लगाने में इस समय जो पाँच हजार रुपए की कटौती की सुविधा उपलब्ध है उसे बढ़ा कर दस हजार रुपए कर दिया जाए।

80. इस समय, वेतन आय का हिस्सा लगाते हुए, पेंशन-भोगियों के मामले में, मानक कटौती उपलब्ध नहीं है। पेंशन-भोगियों को, जो कि बीमरों की वृद्धि के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोगों में से हैं, कुछ राहत देने के लिए मैं उन्हें भी मानक कटौती का लाभ देना चाहता हूँ।

81. अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं उनकी विदेश में उपाजित अग्रगण्य के 25 प्रतिशत भाग के बराबर कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ, यदि यह धनराशि भारत में विदेशी मुद्रा में लार्ड जाए। यह उपबंध चालू निर्धारण वर्ष और उससे बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि जीवन बीमा और भविष्य निधियों आदि के जरिये खिलाड़ियों द्वारा की गई बचतों के संबंध में ऊँची दर से कटौती की अनुमति होनी चाहिए, जैसी कि इस समय लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, संगीतज्ञों और अभिनेताओं के मामले में उपलब्ध है। इस प्रकार खिलाड़ी लोग जीवन बीमा और भविष्य निधियों में किए गए अंशदानों के लिए अपनी व्यावसायिक आय के 40 प्रतिशत तक और अपनी बाकी आय के 30 प्रतिशत तक, और कुल मिलाकर अधिक से अधिक 50,000 रुपए तक की कटौती के हकदार होंगे।

82. 1978 में, विज्ञापन, प्रचार और बिक्री संयोजन पर किए गए व्यय की कटौती-योग्य राशि के बारे में कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे।

311 GI/80-2

इन प्रतिबंधों ने ख़ास तौर से यशु और सभ्य कारबार को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए, मैं इन प्रतिबंधों को हटा देने का प्रस्ताव करता हूँ।

83. इस समय, भुर्गीपालन और डेरी व्यवसाय तथा पशुपालन में होने वाली आय, उसके 33 1/3 प्रतिशत या इस हजार रुपए से भी कम हो जायेगी वहाँ तक आयकर से मुक्त है। मैं सोचता हूँ कि अब समय आ गया है कि जब इन स्त्रोतों में आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी राष्ट्रीय खजाने में कुछ ज्यादा अंशदान दें। इसलिए मैं इस प्रकार की आय के संबंध में की जाने वाली कटौती को ऐसी आय के एक-तिहाई भाग अथवा पंद्रह हजार रुपए में से जो भी कम हो उस तक सीमित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

84. इस समय, धन-कर लगाने के प्रयोजनों के लिये कृषि संपत्ति को कराधेय धन में शामिल किया जाता है। उस समय जब कि कृषि-संपत्ति को कर की परिधि में लाया गया था। यह आशा की गई थी कि यह कृषक समुदाय के समृद्ध वर्ग से साधन जुटाने का एक गणकन माध्यम होगी। परन्तु पिछले दस सालों में हमें जो अनुभव हुआ है वह बहुत ही निराशाजनक है। कृषि संपत्ति पर वसूल किए जाने वाले धन-कर की राशि प्रतिवर्ष प्रायः एक करोड़ रुपए से कम रही है। कृषि भूमि के मूल्यांकन ने कई कठिनाइयाँ पैदा कर दी हैं जिनके कारण परेशान किए जाने की शिकायतें बहुत आई हैं। चूंकि यह कर अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति में पूरी तरह असफल रहा है, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कृषि-संपत्ति पर धन-कर लगाना बंद कर दिया जाए, किन्तु चाय, काफी, रबड़ और इलायची के बागानों के मालिकों के मामले में यह पूर्ववत् लागू रहेगा। मुझे विश्वास है कि इस कदम का हमारे किसान भाइयों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया जाएगा।

85. मैं आय-कर अधिनियम में कुछ संशोधन करना चाहता हूँ जिनका उद्देश्य ऐसे कुछ न्यायालयिक निर्णयों को प्रभावहीन करना है जिनके कारण करदाताओं को अनचाहा लाभ मिल गया है। वित्त विधेयक में प्रत्यक्ष करों में संशोधन के लिए और भी कुछ प्रस्ताव हैं जिनका अधिक महत्व नहीं है। उनको स्पष्ट करने में मैं सभन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा।

86. प्रत्यक्ष करों के संबंध में दरें घटाने और अन्य रियायतें देने से साधारणतया राजस्व में कमी होनी चाहिए। किन्तु मेरा विचार है कि दरें घटा देने से कर संबंधी कानूनों के पालन में बहुत ज्यादा सुधार होगा। कर-परिवर्तन की तरकीबों को निष्फल करने के लिए वैधानिक संशोधन कर देने से और अग्रिम कर के उपबंधों में परिवर्तन कर देने से अधिक राजस्व प्राप्त होना चाहिए। आय-कर और धन-कर संबंधी सभी प्रस्तावों के समग्र प्रभाव को मोटे तौर पर आंकने पर मुझे तो ऐसा लगता है कि राजस्व की कोई हानि नहीं होगी। किन्तु मैं यह मानता हूँ कि आय-कर के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के परस्पर हिस्सों में कुछ समायोजन करने की आवश्यकता हो सकती है। ये समायोजन वर्ष के दौरान कर-संग्रह की प्रवृत्तियों को देखते हुए किए जाएंगे।

87. उधार देने की वरों में ऊपर की ओर समायोजन करने से अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव कम हो जाने चाहिए। अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 30 जून, 1980 के बाद अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपाजित ब्याज के संबंध में ब्याज-कर फिर से लागू कर दिया जाए। इस कर के व्याप्ति-क्षेत्र को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि उसमें बड़ी-बड़ी अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्वित्त निगम द्वारा प्राप्त ब्याज की राशियों को भी शामिल किया जा सके। यह कर पहले की तरह ब्याज को प्रभावी राशि पर 7 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा। इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 217 करोड़ रुपए और 1980-81 में लगभग 108.5 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

88. लक्ष्मरी होटलों में आवास और मनोरंजन पर लगे जाये कि, जाने वाले व्ययों को रोकने के उद्देश्य से, मैं एक नया कर लगाने के लिए चालू सत्र में ही एक विधेयक पेश करना चाहता हूँ, यह कर उन होटलों की सकल प्राप्तियों पर 15 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा जिनमें एक एकल कमरे का न्यूनतम किराया 75 रुपए प्रतिदिन है। यह नया कर 1 सितम्बर, 1980 से लागू करने का प्रस्ताव है। इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 12 करोड़ रुपए और 1980-81 में कोई 5 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

89. अब मैं अप्रत्यक्ष कर संबंधी अपने प्रस्तावों पर आता हूँ। अपने प्रस्ताव तैयार करने हुए मैंने निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखा है। जहां तक अतिरिक्त साधन जुटाना प्रतिबाध्य है, वहां तक यह काम हम प्रकार किया जाए कि किसी भी वस्तु पर बोझ बहुत ज्यादा न बढ़े। इस धारणा के अनुसार, हमारे लघु उद्योग क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। रोजगार और निर्यात की प्रचुर क्षमता रखने वाले उद्योगों को शुल्क ढांचे में समुचित फेर-बदल करके, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ग्राम उपभोग की कुछ वस्तुओं पर से शुल्कों का बोझ कम कर दिया जाना चाहिए, या बिल्कुल ही हटा दिया जाना चाहिए।

90. शुल्क से ही मैं सम्मानित सदस्यों को यह बताना निश्चित कर देना चाहता हूँ कि मेरे प्रस्ताव बहुत संतुलित हैं। ग्राम तौर पर यह किया जाता रहा है कि कुछ चुकी हुई वस्तुओं पर नए शुल्क लगाए जाते हैं या पुराने शुल्कों की दरों में वृद्धि कर दी जाती है। मगर मैंने इस तरीक़ीब से बचने की कोशिश की है।

91. हम वर्ष मैंने अतिरिक्त कराधान के भार को विभिन्न प्रकार की बहुत ज्यादा वस्तुओं पर हल्का हल्का फैलाने की कोशिश की है और यह भी ध्यान रखा है कि ग्राम उपभोग की वस्तुओं पर इसका असर न पड़े। मैं इस उद्देश्य को विशेष उत्पाद-शुल्क के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ जो अब भी उत्पाद शुल्क योग्य सभी वस्तुओं पर आधारिक उत्पाद-शुल्क के 1/20 की दर से लगता है, लेकिन बहुत सी चीजों को इससे मुक्त रखा गया है। मेरे प्रस्ताव के अनुसार, विशेष उत्पाद-शुल्क उन वस्तुओं पर लगाया जाएगा जो इस समय इससे मुक्त हैं और इसकी दर लागू आधारिक उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दरों के 1/20 भाग के बराबर होगी। तथापि कुछ चीजें आगे भी पूरी तरह शुल्क मुक्त रहेंगी। इस प्रकार मोटर स्प्रिंटर, जिसमें तैप्या, मिट्टी का तेल, उच्च गति डीजल तेल, हल्का डीजल तेल और द्रवित पेट्रोलियम गैस शामिल हैं, तथा कोयले और बिजली पर विशेष उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा, बिया-सलाई, बनस्पति और टेरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं पर भी विशेष उत्पाद-शुल्क नहीं लगाया जाएगा। जहां प्रभावी आधारिक शुल्क के 1/20 की दर से पहले ही विशेष उत्पाद-शुल्क लग रहा होगा उनके संबंध में मैं दर को बढ़ाकर प्रभावी आधारिक शुल्क का 1/10 करने का प्रस्ताव करता हूँ। लेकिन यह वृद्धि भट्टी के तेल, एस्काट, बिटुमिन और कोलतार, अन्यथा अविनिष्ट पेट्रोलियम उत्पाद और भस्मीभूत पेट्रोलियम कोक पर लागू नहीं होगी। चीनी और संसाधित बनस्पति निर्गन्ध तेलों पर भी बढ़ी हुई दर से शुल्क नहीं लगेगा। इस समय सिगरेटों पर विशेष उत्पाद-शुल्क बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन अब उन पर आधारिक उत्पाद-शुल्क के 1/10 के हिसाब से विशेष उत्पाद-शुल्क लगेगा। इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में 197.71 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। विशेष उत्पाद-शुल्क संबंधी प्रस्तावों के फलस्वरूप, आयातित वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों के रूप में, 16.75 करोड़ रुपए की और प्राप्ति होगी।

92. सोडा ऐश और कास्टिक सोडा की लगातार कमी रहने के कारण बाजार में इन पर बहुत ज्यादा प्रीमियम मिलता है। मैं इन उत्पादों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत मूल्यानुसार बढ़ाकर इस प्रीमियम के कुछ हिस्से को बटोर लेना चाहता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि सांड (स्टार्च) पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क की दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए।

मेरा क़रीब से दो आयातित उत्पाद इस तरह आयातित उत्पादों के साथ समान स्तर पर आ जायेंगे जिन पर सामान्य रूप से इस मूल्य 15 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से उत्पाद-शुल्क लगता है। संक्षिप्त रखे पर इस समय 5 प्रतिशत मूल्यानुसार की बहुत नीची दर से शुल्क लगता है। राजस्व के उपाय के रूप में मैं संक्षिप्त रखे पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसी प्रकार विनिष्ट तैयारियों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क की दरों को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है। इन उपायों से एक पूरे वर्ष में 18.93 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

93. राजस्व प्राप्त करने की दृष्टि से ही मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि शीरे पर इस समय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत जो 8 प्रतिशत के हिसाब से शुल्क लगता है उसकी बजाय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ में ही एक अलग मद के अन्तर्गत 30 रुपए प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से मात्रानुसार शुल्क लगाया जाए। लेकिन यह शुल्क बैक्सीम पैंत वाली चीनी मिलों में उत्पादित शीरे पर ही लगाया जाने का प्रस्ताव है। खाण्डसारी के कारखाने में उत्पादित शीरा जो खाने के काम भी आता है, शुल्क-मुक्त रखा जाएगा। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप एक वर्ष में 4.24 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होने का अनुमान है।

94. अब मैं उन प्रस्तावों की ओर आता हूँ जो देशी उद्योग के कनिष्ठ क्षेत्रों को पहले से अधिक मात्रा में संरक्षण देने के लिए तैयार किए गए हैं। पहला प्रस्ताव आडिओकैस्सेट्री टेप्पीकारों के संबंध में है; यह मद लघु क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखी गई है। इस मद के आयातों के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए मैं आयातों पर लगने वाले सीमा शुल्क को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 120 प्रतिशत मूल्यानुसार करना चाहता हूँ। मेरा दूसरा प्रस्ताव आयातित कोरी रंगीन पाजिटिव मिनेमा फिल्मों के बारे में है जिनके संबंध में आधारिक सीमा शुल्क को 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया प्रति लीनियर मीटर कर देने का प्रस्ताव है ताकि हमारे सरकारी क्षेत्र का ऐसी फिल्म बनाने का कारखाना आयातित फिल्मों के मुकाबले में ठहर सके। देशी कम्प्यूटर उद्योग को संरक्षण देने के उद्देश्य से मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि आयातित कम्प्यूटरों पर लगने वाले प्रति-संतुलनकारी शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए। इन उपायों से एक पूरे वर्ष में लगभग 1.83 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति होने की उम्मीद है।

95. अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में मेरा राजस्व सम्बन्धी केवल एक प्रस्ताव और है। इसका सम्बन्ध यात्रियों के सामान से है। जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं, 1978 में यात्रियों के सामान पर दो आने वाली छूटों को काफी उदार बना दिया गया था और थोड़े समय के लिए विदेश यात्रा पर जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए सामान्य रूप से ये छूटें उबार बना दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 1,000 रुपए तक के मूल्य के सामान को बिना शुल्क दिए और 2000 रुपए तक के मूल्य की वस्तुओं को शुल्क अर्ध करके लाने की अनुमति थी। इस उदारीकरण के बावजूद, कई यात्रियों द्वारा यात्री-सामान की किस्म की वस्तुओं का अनुमत सीमाओं से कहीं अधिक मात्रा में बराबर आयात किया जाता रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि लोग विदेशी चीजों के पीछे पागल से हो रहे हैं और इन वस्तुओं को भारत में बेचने पर काफी मुनाफा होता है। अनुमत सीमाओं से अधिक ऐसे यात्री सामान का आयात किए जाने की स्थिति में व्यापारनिर्णयन की कार्यवाही आरम्भ करना जरूरी हो जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे अन्तर-राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्रियों को निकासी की गति धीमी हो जाती है। मैंने इस समस्या पर विचार किया है और इस संबंध में मैं दो प्रस्ताव रख रहा हूँ। पहला तो विण्ड रूप से राजस्व सम्बन्धी उपाय के रूप में है, जिसके अनुसार निःशुल्क सीमा से अधिक यात्री-सामान की वस्तुओं पर शुल्क की दर 120 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 150 प्रतिशत मूल्यानुसार की जा रही है। यह उपाय तत्काल लागू हो जाएगा और

इस पूरे वर्ष में 20 करोड़ रुपए की प्रतिरक्षित प्राप्ति होगी। दूसरे उपाय में, जो भीष्ट ही लागू किया जाएगा, अनुमत सीमाओं से अधिक आयात किए गए यात्री-सामान पर 320 प्रतिशत की समान दर पर शुल्क लगाया जाएगा। अर्थात् यह शुल्क, निःशुल्क अथवा 150 प्रतिशत का शुल्क देकर लाए जा सकने वाले यात्री-सामान से अधिक सामान के आयात पर लगाया जाएगा। फिलहाल ऐसी वस्तुओं का लाया जाना बिना लाइसेंस का आयात माना जाता है और इसलिए उन्हें जप्त किया जा सकता है, अथवा उन पर भूमि या वण्ड लगाया जा सकता है ताकि इन वस्तुओं को बेचने पर जो मुनाफा होगा उसे शून्य कर दिया जाए। शुल्क की दर बढ़ाने का उद्देश्य यह है कि न्यायनियमित की लंबा समय लेने वाली प्रक्रिया से गुजरना न पड़े और इन जमानों और वण्डों के स्थान पर इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। लेकिन ऐसी वस्तुओं के संबंध में जो स्पष्टतः व्यापारिक किस्म की होंगी अब भी दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

98. मेरे कुछ और भी प्रस्ताव हैं जो अनिवार्यतः करों को युक्ति-मग्न बनाने के उपायों के रूप में हैं। पहला वातित जल (एयरटिड वाटर) के संबंध में है। प्रस्ताव है कि सरलीकरण के उद्देश्य से, उत्पाद-शुल्क के प्रयोजन में कैफीन वाले और बिना कैफीन के वातित जल के वर्तमान भेद को समाप्त कर दिया जाए और इसके बजाए सभी प्रकार के सुवासित वातित जल पर 40 प्रतिशत मूलानुसार की समान दर से शुल्क लगा दिया जाए। इस प्रस्ताव का राजस्व प्रभाव नगण्य होगा।

97. मैंने 1979 के बजट में, दियासलाई उद्योग पर लागू उत्पाद-शुल्कों के ढांचे में किए गए परिवर्तनों से उत्पन्न समस्याओं पर काफी विचार किया है। यद्यपि कुटीर उद्योग क्षेत्र को दिए गए लाभों को बराबर बनाए रखने की स्पष्ट आवश्यकता है, लेकिन इस का अर्थ यह नहीं कि अत्यधिकृत मध्यमवर्ती क्षेत्र को कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में घुसपैठ करने दी जाए इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कि शुल्क की नीची दर का लाभ केवल कुटीर उद्योग क्षेत्र के प्रमत्ती एककों को ही प्राप्त हो, मेरा यह प्रस्ताव है कि रियासनाइयों पर शुल्क की रियायत को भू-मोड़ित खेती वाली और खादी ग्रामोद्योग आयोग, राज्यों के अधिकारियों तथा पंजीकृत सहकारी समितियों को बेची गई या उनके माध्यम से बेची जाने वाली दियासलाई तक सीमित कर दिया जाए। इसके साथ-साथ, मुझे कुटीर क्षेत्र के संबंध में शुल्क की रियायती दर पर दियासलाई की निकासियों की मौजूदा सीमाओं का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। अतः मैं कुटीर क्षेत्र के एकको ढांचा किए गए उत्पादन पर लगी मौजूदा सीमाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे विश्वास है कि इन मिले जुले उपायों के कुटीर क्षेत्र के दियासलाई उद्योग का तेजी से विकास होगा।

98. बीड़ी उद्योग के उन निर्माताओं द्वारा किये जाने वाले कदाचार की शिकायतें मिली हैं जो बिना ब्राण्ड की बीड़ी के क्षेत्र पर लागू छूट की उदारसीमा का, जो इस समय 60 लाख बीड़ी प्रति निर्माता प्रतिवर्ष है, नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इस कदाचार की संभावनाओं का कम करने के उद्देश्य से मेरा यह प्रस्ताव है कि छूट की सीमा को कम करके बिना ब्राण्ड की 30 लाख बीड़ी प्रति निर्माता प्रतिवर्ष कर दिया जाए। इससे अब भी वे निर्माता उत्पाद-शुल्क के जाल से बाहर रहेंगे जो वास्तव में छोटे हैं और अपना धंधा खूद करते हैं। इसका उद्देश्य कोई राजस्व उगाहना नहीं है।

99. वित्त विधेयक के कुछ उपबन्धों का उद्देश्य कनिष्ठ केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ की मदों को युक्तिमग्न बनाना या उनकी स्पष्ट परिभाषा करना है, ताकि उन मदेहों या कठिनाइयों को दूर किया जा सके जो हमारे ध्यान में आई हैं। इन उपायों का व्योम बजट-पत्रों में देखा जा सकता है।

100. अब मैं प्रत्यक्ष करों में दो नए नतीजे रियायतों की धारा बताऊँ। हमारी अर्थव्यवस्था में छोटे निर्माता की भूमिका काफी महत्वपूर्ण

है। मैं चाहता हूँ कि बड़े निर्माता की तुलना में उसकी प्रतियोगितात्मक स्थिति में और सुधार हो और इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था का उद्यम-विषयक आधार और व्यापक हो। यही एक मात्र ऐसा उपाय है जिससे हम अधिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोक सकें हैं। उत्पाद-शुल्क योग्य 70 वस्तुओं के निर्माताओं पर लागू होने वाली शुल्क संबंधी रियायतों की एक योजना पहले से ही मौजूद है जिसके अन्तर्गत एक वर्ष में 5 लाख रुपए तक के मूल्य की निकासियों को शुल्क से छूट दी गई है। मैं अब इस रियायत को दो पहलुओं में उदार बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। पहला पहलू तो यह है कि मैं इस योजना के अंतर्गत वस्तुओं के दो और समूहों को शामिल करना चाहता हूँ। ये हैं: रसायन अर्थात् सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लोचिंग पाउडर, केलिंगम कार्बाइड तथा कृत्रिम व सिंथेटिक रेसिन और प्लास्टिक सामग्री। इसके अलावा कागज और कागज के गत्ते से सम्बद्ध क्षेत्र को और व्यापक बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण रियायत, जिसे मैं वेना चाहता हूँ यह है कि इस योजना के अन्तर्गत आने वाली सभी वस्तुओं के बारे में 5 लाख रुपए और 15 लाख रुपए के बीच की निकासियों पर इस समय जो सामान्य उत्पाद-शुल्क की दर लगी है उसके मुकाबले केवल उसकी तीन-चौथाई दर लागू होगी। इस उपाय से बड़ी संख्या में छोटे निर्माताओं को लाभ पहुंचेगा। इसके परिणामस्वरूप पूरे वर्ष में राजस्व की लगभग 6.50 करोड़ रुपए की हानि होगी।

101. पिछले वर्ष के बजट में एक ऐसा परिवर्तन किया गया था जिसका केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ की अवशिष्ट मद 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के बहुसंख्यक लघु निर्माताओं पर प्रभाव पड़ना था। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि निःशुल्क निकासियों की मात्रा 30 लाख रुपए से घटाकर 15 लाख रुपए कर दी गई थी। मैंने इस परिवर्तन का तब भी विरोध किया था। ऐसे छोटे निर्माताओं को पेश आने वाली कठिनाइयों को दूर रखने के उपाय के रूप में मैं 30 लाख रुपए वार्षिक तक की निकासियों को उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। दूसरे शब्दों में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ की मद 68 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के छोटे निर्माता जिनके संयंत्र और मशीनों पर 10 लाख रुपए से अधिक पूंजी न लगी हो, एक वित्तीय वर्ष में 30 लाख रुपए तक के माल की पहली निकासी पर शुल्क से पूरी छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे, बशर्ते कि उससे पिछले वर्ष उनकी निकासियों का मूल्य 30 लाख रुपए से अधिक न हो। चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग के लिए पूरी छूट का पात्र निकासियों की मात्रा तदनुसार कम करके निर्धारित की जाएगी। इस रियायत से पूरे वर्ष में 2.4 करोड़ रुपए की हानि होने की संभावना है।

102. देश में कागज और संबद्ध उत्पादों की कमी है और इस क्षेत्र में तत्काल कोई नई पूंजी नहीं लगाई जा रही है। उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए छोटे-एकक बहुत कुछ कर सकते हैं। अतः इन्हें प्रोत्साहन देने के लिए मैं उन छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादित कागज और कागज के गत्ते पर लागू मौजूदा 30 प्रतिशत मूलानुसार की दर के स्थान पर 20 प्रतिशत मूलानुसार की रियायती दर लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ जिन कारखानों की पिछले वित्तीय वर्ष की निकासियों की मात्रा 300 मेट्रिक टन कागज और कागज के गत्ते से अधिक न हो। इस रियायत से पूरे वर्ष में एक करोड़ रुपए से कुछ कम की हानि होगी।

103. इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में रोजगार और निर्यात की काफी संभावनाएं हैं। हमारे पास आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता मौजूद है और उचित राजकोषीय प्रोत्साहनों के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग का विकास करने के प्रयोजन से इनका बड़े पैमाने पर लाभ उठाया जाना चाहिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लघु निर्माता के लिए आगे बढ़ने का बड़ी गुंजाइश है। अतः इस उद्योग के लिए मैं शुल्कों में कुछ रियायतों का प्रस्ताव करता हूँ। पूंजीगत मशीनों और उपकरणों जैसी विनिवृष्टि मदों पर, जिनकी इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को आवश्यकता होती है और जिनका देश में उत्पादन नहीं होता, सीमा शुल्क में कटौती कर दी जाएगी। ऐसी मदों पर सीमा-शुल्क की वर्तमान दर (जो कुछ मामलों में 80 प्रतिशत मूलानुसार तक ऊंची है)

घटाकर कुल 25 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दी जाएगी। इसी प्रकार, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिए आवश्यक विनिर्दिष्ट कच्चे माल और संघटकों पर लगने वाले सीमा-शुल्क की दरों के वर्तमान स्तर को (जो कुछ मामलों में 200 प्रतिशत मूल्यानुसार से भी ऊँचा है) घटाकर 45 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए और प्रतिसंतुलनकारी-शुल्क भी लगना रहे जहाँ मर 68 के अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क लगता है। इन रियायतों से राजकोष को पूरे वर्ष में 4.7 करोड़ रुपए की हानि होगी।

104. अन्य देशों के अनुभव से पता चलता है कि इलेक्ट्रानिकी की उपभोक्ता वस्तुओं के विकास से कुछ समय बाद इलेक्ट्रानिकी की अन्य प्रत्याधुनिक वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी सुविधा हो जाती है। टेलीविजन संसार और शिक्षा का एक सशक्त माध्यम है। इस विचार से कि अधिक से अधिक लोगों को इस माध्यम से लाभ हो, मैं सस्ते टी.वी. सेटों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को 15 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटाकर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार और इसी प्रकार अन्य टी.वी. सेटों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को 30 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटाकर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन रियायतों से एक वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

105. इसी प्रकार रेडियो भी शिक्षा और मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है और इसका उपयोग अधिक व्यापक रूप से किया जाता है। सरकार का विचार है कि एक और दो बँड वाले रेडियो सेटों को खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। ऐसे सेटों पर लगने वाली लाइसेंस फीस बहुत घुबसी रही है और इससे ग्रामीण जनता द्वारा रेडियो सेट खरीदने के मार्ग में रुकावट आती है। अतः मैं एक और दो बँड वाले रेडियो सेटों तथा ट्रांसिस्टर सेटों पर से यह लाइसेंस फीस बिल्कुल हटा देने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे विश्वास है कि इसका सर्वत्र स्वागत होगा। इस छूट से सरकार को लगभग 4 करोड़ रुपए की हानि होगी।

106. हमारा कम्प्यूटर उद्योग अन्य देशों की तुलना में अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है। देश में कम्प्यूटरों के उत्पादन को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के विचार से मैं देश में बने कम्प्यूटरों पर लगे उत्पाद-शुल्क को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटाकर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ।

107. जहाज-निर्माण एक उच्च प्राथमिकता वाला उद्योग है और वह देश को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस समय भारतीय जहाज-निर्माण उद्योग को विदेशी जहाज निर्माताओं से प्रतियोगिता करने में अधिकाधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं जहाज बनाने वाले भारतीय कारखानों में बने समुद्रगामी जहाजों के लिए उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। चाणू वर्ष में इस राहत के कारण लगभग 5 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।

108. सम्मानित सदस्य जानते हैं कि उद्योगों की पूंजीगत लागत का कम करने के उपाय के रूप में सरकार देशी दृष्टिकोण रहित कुछ चुनी हुई मशीनों के संबंध में आयात-शुल्क को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार तक घटाने की पद्धति का अनुसरण करती रही है। इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए मैं इस वर्ष पूंजीगत मशीनों की बारह और मशनों पर लगे आयात-शुल्क को 25 प्रतिशत मूल्यानुसार तक घटाने का प्रस्ताव करता हूँ। मशीनों की इन मशों में मुद्रा उद्योग में काम आने वाली हार्ड स्पीड लैटर प्रेस, रोटररी और आफसेट रोटररी प्रिंटिंग मशीनों, मोनों/लाइनों टाइप कास्टिंग मशीनों आदि जैसी पांच मशें शामिल हैं। इन रियायतों से पूरे वर्ष में 1.84 करोड़ रुपए के राजस्व से हाथ धोना पड़ेगा।

109. हार्ड प्रेशर गैस मिलिण्डर की लागत गैस उद्योग की कुल पूंजीगत लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। इस पूंजी परिकल्पना को कुछ हद तक कम करने की दृष्टि से मैं हार्ड प्रेशर गैस मिलिण्डरों के निर्माण के लिए आयात की जाने वाली इस्पात की ट्यूबों का सीमा-शुल्क से

पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। साथ ही मैं ऐसे सिलिण्डरों पर लगने वाले वर्तमान 15 प्रतिशत मूल्यानुसार उत्पाद-शुल्क को घटाकर 8 प्रतिशत मूल्यानुसार तक करने का भी प्रस्ताव करता हूँ जिन पर मर 68 के अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क लगता है। इन दोनों उपायों से कुल मिलाकर पूरे वर्ष में 1.89 करोड़ रुपए की हानि का अनुमान है।

110. मेरा एक सामान्य रूप से लागू होने वाला प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य उन उत्पाद-शुल्क-योग्य वस्तुओं के निर्माणों का सुविधा प्रदान करना है जिनके निर्माण में ऐसी वस्तुएं काम में लाई जाती हैं जिन पर उत्पाद-शुल्क लगता है। ऐसे मामलों में राहत पहुँचाने के लिए इस समय दो तरीके अपनाए जाते हैं। इनमें एक है जिसे मुजरे का तरीका (सेट आफ प्रोसीजर) कहा जाता है। दूसरा है केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों के नियम 56 क के अन्तर्गत प्रोफार्मा क्रेडिट का तरीका। प्रोफार्मा क्रेडिट के तरीके को प्रायः निर्माताओं के लिए अधिक लाभप्रद और कम कष्टकर माना जाता है। अतः मैं मुजरे के तरीके के आधार पर ही जहाँ बारी वर्तमान रियायतों के स्थान पर प्रोफार्मा क्रेडिट के तरीके के आधार पर एसी ही रियायतें देने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस उपाय का उद्योग द्वारा स्वागत किया जाएगा।

111. मुझे सम्मानित सदस्यों को यह याद दिलाते हुए थोड़ा कष्ट हो रहा है कि पिछले वर्ष के बजट में ग्राम-उपभोग की कई वस्तुओं पर काफी हद तक उत्पाद-शुल्क बढ़ा दिया गया था। मैं इस प्रवृत्ति को उलट देने का प्रस्ताव करता हूँ। अतः

— तीस प्राण-रक्षक दवाओं को उत्पाद-शुल्क से बिल्कुल छूट दे दी गयी है। इन दवाओं की सूची की समय-समय पर समीक्षा की जानी रहेगी ताकि जबरन पड़ने पर इसमें और दवाएं भी जोड़ी जा सकें।

— कंट्रोल का कपड़ा समाज के कमजोर वर्गों के लिए होता है और इसकी कीमत कम से कम होनी चाहिए। इस लिए मैं कंट्रोल के कपड़े को उत्पाद-शुल्क से बिल्कुल मुक्त कर देने का प्रस्ताव करता हूँ।

— सूती और सूती-विरक्त होजिरी, जिनमें बनियानों जैसी मशें शामिल हैं, अपेक्षाकृत कम मूल्य की होती हैं और होजिरी की इन मशों पर 8 प्रतिशत की दर से उत्पाद-शुल्क लगता है। मैं इन्हें उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर देने का प्रस्ताव करता हूँ।

— सार्इकिल गरीब आदमी की सवारी है। इसलिए मैं सार्इकिलों और मर 68 के अन्तर्गत आने वाले सार्इकिलों के पुजों को उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

— मिर्च की मशीन के बिना गृहिणी का काम बिल्कुल नहीं चल सकता और समाज के कमजोर वर्ग इन मशीनों से रोजी भी कमाते हैं। इन पर उत्पाद-शुल्क से बिल्कुल छूट दे दी जाएगी।

— प्रेशरकुकर से गृहिणी के रोजमर्रा के काम में मेहनत की काफी बचत होती है और साथ ही इससे ईंधन भी बचता है। प्रेशरकुकरों पर इस समय 15 प्रतिशत की दर से जो उत्पाद-शुल्क लगता है मैं इसे कम कर के 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

112. मैं रोजमर्रा के काम आने वाली कई और वस्तुओं पर लगे उत्पाद-शुल्क में काफी कटौती करने का प्रस्ताव करता हूँ। अतः

— नहाने के साबुन की मस्ती किस्मों पर उत्पाद-शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा;

— टयू वेस्ट पर लगने वाला उत्पाद-शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा;

— बैक्यूम और तैम वाले 60 बाट सक के बल्बों पर उत्पाद-शुल्क 15 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

113. मुझे विश्वास है कि इन काफी रियायतों का जितने राजकोष को पूरे वर्ष में लगभग 15 करोड़ रुपए की हानि होगी, संसद और जनता द्वारा स्वागत किया जाएगा। मैं यह भी आशा करता हूँ कि उद्योग और व्यापारी वर्ग उपभोक्ता के साथ उचित व्यवहार करेंगे और उत्पाद-शुल्क में की गई इन कटौतियों का फायदा अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे।

114. हमारी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में टैक्सियों को डीजल से चलाने के सम्बन्ध में प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। हम वायदे को पूरा करने और टैक्सी मालिकों को अपनी टैक्सियों में डीजल इंजन लगवाने के लिए प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से मैं पेट्रोल से चलने वाली टैक्सियों के इंजनों को डीजल में बदलने की सूरत में डीजल इंजनों को उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

115. मेरे दूसरे प्रस्ताव का उद्देश्य सार्वजनिक रिक्षाचालकों को राहत देना है। मोटर से चलने वाले रिक्षों पहले से ही उत्पाद-शुल्क से मुक्त हैं। मोटर के बिना चलने वाले रिक्षों को मोटर से चलने वाले रिक्षों में बदलने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं इस काम में आने वाले अन्तर्वहन इंजनों को उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदस्य मेरे इस प्रस्ताव का स्वागत करेंगे क्योंकि इससे निश्चय ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम शारीरिक श्रम को काम करने और सवारी के इस सस्ते साधन को बढ़ावा देने के लिए कितने उत्सुक हैं।

116. अप्रत्यक्ष करों की बात समाप्त करने से पूर्व मुझे नीति सम्बन्धी एक प्रमुख घोषणा करनी है। पिछले बीस वर्षों से लोग प्रत्यक्ष करों की भांति सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के मामलों के निपटारे के लिए एक स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की मांग करते रहे हैं। हाल में संसद की प्राक्कनन समिति ने भी इस मांग का समर्थन कर दिया है। गत वर्षों में सरकार इस प्रकार की किसी व्यवस्था के पक्ष में नहीं थी क्योंकि ऐसा महसूस किया जाता था कि अप्रत्यक्ष करों के मामले में ऐसा करना उचित नहीं होगा और यह भी कि वर्तमान विभागीय तंत्र का वृष्टिकोण वस्तुतः वस्तुपरक रहता है। मेरे विचार में अब ऐसा समय आ गया है जब हमें इस आम राय को प्रामाण्यता के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए जो इस नीतिवाक्य पर आधारित है कि न्याय न केवल किया ही जाए बल्कि किया हुआ दिखाई भी दे। इसी भाव में प्रेरित होकर वित्त विधेयक में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण के मामले में अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है। यह न्यायाधिकरण उस कार्यपालक तंत्र से बिल्कुल स्वतंत्र होगा जिस पर राजस्व विषयक कानूनों के राजमर्ग के प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि संसद और व्यापार तथा उद्योग इस उपाय का तहे दिल से अनुमोदन करेंगे।

117. मेरे कर प्रस्तावों से पूरे वर्ष में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों से 223.22 करोड़ रुपए की और सीमा शुल्कों से 39.58 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। मैंने जिन राहतों की घोषणा की है उनमें से 34.75 करोड़ रुपए की राहतें केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत और 7.93 करोड़ रुपए की राहतें सीमा-शुल्क के अन्तर्गत आती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों से 188.47 करोड़ रुपए और सीमा शुल्कों से 31.65 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति होगी। पूरे वर्ष में इससे केन्द्रीय राजकोष में 144.85 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी और राज्यों का हिस्सा 75.27 करोड़ रुपए होगा।

118. जिन मामलों में परिवर्तनों की अधिसूचनाओं द्वारा 19 जून, 1980 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है, उन अधिसूचनाओं की प्रतियां यथासमय मंत्रालय पर रख दी जाएंगी।

119. अब मैं अपने सम्मानित सहयोगी मंचार मंत्री की ओर से कुछ शब्द कहना चाहूंगा। डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को मंत्रगार्ड भत्ते की श्रद्धांगी किए जाने और उनके लिए उत्पादकता में जुड़ा बोनस संजूर किए जाने के परिणामस्वरूप विभाग का कार्यचालन व्यय काफी बढ़ गया है। इसलिए कुछ चुनी हुई सेवाओं की शुल्क दरों को बढ़ाना जरूरी हो गया है। इन शुल्क दरों में संशोधन करने के प्रस्ताव करने समय सरकार बड़ी सावधानी से ऐसी सेवाओं की शुल्क-दरों में संशोधन करने से दूर रही है, जिनका साधारणतया आम आदमी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट कार्ड और अन्तर्वेशीय पत्रों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी लेकिन न्यूनतम खण्ड पर पत्रों की शुल्क-दर 30 पैसे से बढ़ा कर 35 पैसे की जा रही है। प्रत्येक 500 ग्राम के लिए पामेल की दर 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2.00 रुपए कर दी जाएगी। टेलीफोन कनेक्शन लगाने और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेजाने के प्रभार भी बढ़ाए जा रहे हैं। एक निमाही में 5,000 स्थानीय कालों से अधिक कालों पर मौजूदा 40 पैसे प्रति काल की दर के बजाए 50 पैसे प्रति काल के हिसाब से प्रभार लिया जाएगा। बजट पक्षों के साथ एक ज्ञापन परिचालित किया जा रहा है जिसमें प्रस्तावित शुल्क दरों का विवरण दिया गया है। इस ज्ञापन को देखने से पता चलेगा कि डाक और दूर संचार की अधिकतर सेवाओं के प्रभारों को धृष्टा तथा भी नहीं गया है। प्रभारों में ये परिवर्तन संसद द्वारा वित्त विधेयक पारित कर दिए जाने के बाद अधिसूचित की जाने वाली तारीख से लागू होंगे। प्रस्तावित शुल्क-दर संशोधनों से प्रति वर्ष 27.10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है। वर्ष 1980-81 में लगभग 13 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व का अनुमान लगाया गया है और डाक-तार विभाग का राजस्व अनुमान लगाने समय इसे हिसाब में ले लिया गया है।

120. बजट में प्रस्तावित राहतों को हिमाब में लेने के बाद, कुल मिलाकर कर-प्रस्तावों से चालू वर्ष में, लगभग 282 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति होगी जिसमें से 223 करोड़ रुपए केन्द्र को मिलेंगे। इस प्रकार बजट में 1417 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा जिसे मैं बिना कोई व्यवस्था किए छोड़ देना चाहता हूँ। यह घाटा पिछले वर्ष के घाटे के घाघे से थोड़ा-सा अधिक है। मेरे विचार में इतने घाटे का अर्थ व्यवस्था पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि मानसून की स्थिति सामान्य रही और यदि हम उन ठोस आर्थिक नीतियों पर बराबर अमल करते रहे जो हमने पहले ही शुरू कर रखी हैं, तो हमें इस बात की पूरी आशा है कि कृषि और औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त सुधार होगा जिससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही हम एक दायित्वपूर्ण मुद्रा नीति पर अमल करेंगे जिससे अतुल्यदाक या मट्टेबाजी के प्रयोजनों के लिए, बैंक ऋणों के विस्तार पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।

121. महोदय, वर्तमान सरकार को विरासत में मिली कठिन आर्थिक स्थिति की मजबूरियों के शायरे में रहते हुए, मैंने उन लोगों को राहत देने की भरमक कोशिश की है जिन्हें उसकी सब से ज्यादा जरूरत थी। लेकिन राहतें तो पीछा को कुछ हद तक ही कर सकती हैं और निर्धन समाज की वास्तविक आवश्यकता तो विकास ही है, इसलिए मैंने पूंजी निवेश को उचित प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रयास किया है। सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों क्षेत्रों में अधिक पूंजी-निवेश के द्वारा और खास तौर से विभिन्न भागों में उसके बटवारे से उत्पादन और रोजगार, दोनों में काफी वृद्धि होनी चाहिए। सरकार की विशेष जिम्मेदारी समाज के उन कमजोर वर्गों के प्रति है जिन्होंने बड़े उत्पाद के साथ उसे अपना समर्थन प्रदान किया है। इस वजह से, इनके कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से तैयार किए गए विशेष कार्यक्रमों के द्वारा उनको संरक्षण देने का प्रयास किया गया है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो हम गरीब और मध्यम वर्गों के लोगों की न्यूनतम बुनियादी जरूरतों को पूरा सफल बनाई गई सामाजिक वितरण प्रणाली के ज़रिए निश्चय ही पूरा करेंगे।

देश में एक मजबूत और एकजुट होकर काम करने वाली सरकार के आ जाने में मौजूदा उत्पादन क्षमता का पूरा पूरा उपयोग हो सकेगा।

122. देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, विकास और सामाजिक न्याय के पथ पर पुनः अग्रसर करने की प्रक्रिया में भेरा बजट एक बित्तियोगदान है। लेकिन इसकी सफलता उन सभी लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है जो खेती-खलिहानों, मिलों-कारखानों, बिजलीघरों, बंदरगाहों, रेलों और कोयला खानों आदि विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। इस देश की जनता को इन उद्देश्यों का पूरा करने में वर्तमान सरकार की सक्षमता के बारे में बड़ी आशाएं हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इस कार्य में सच्चे मन से अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। हम सब का यह समान प्रयास होना चाहिए कि हम दलगत पूर्वाग्रहों और भावधर्मों से ऊपर उठ कर जन-उत्साह का विकास कार्यों के लिए उपयोग करें।

ए० सी० तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Budget Division)

Budget 1980-81

SPEECH OF

MINISTER OF FINANCE

New Delhi, the 18th June, 1980

No. M of F (DEA) u. o. No. F. 15(1)-B(D)/80.

(PART 'A')

Sir,

I rise to present the regular Budget for the year 1980-81.

2. Presenting the interim Budget in March this year I gave an account of the poor shape of our national economy and the magnitude of the task facing the nation. The Economic Survey presented to the House last week confirms the brief review made by me in March. As it gives a detailed account of the present condition of the Indian economy and its problems and prospects, I shall content myself with highlighting only a few aspects in order to give the House an idea of the gravity of the economic problems faced by this Government, the action it has taken so far to solve them and the need for other measures some of which I shall outline in the course of this speech.

3. The most important and disconcerting fact about the Indian economy is that the gross national product declined in 1979-80 by about 3 per cent. A fall in agricultural production of about 10 per cent and a reduction of about one per cent in industrial production were responsible for this outcome. The set-back in agriculture was partly on account of the severe drought which affected large parts of the country. The decline in industrial production was mainly the result of a serious deterioration in the infrastructure.

4. The performance of power, coal and railway sectors was one of the most serious deficiencies on the economic scene. No doubt the drought was responsible for a decline of 2.2 per cent in hydel production but what stands out is the inability to meet increased demand through increased thermal generation despite substantial additions made to generating capacity in the past three years. Inadequate supply of coal and its poor quality, poor maintenance, equipment damage resulting in increasing planned and unplanned outages and poor management were responsible for the decline in the percentage of thermal capacity utilisation to as low as 45 per cent.

5. In coal again it was the same story. Despite massive investments the production of coal and lignite in 1979-80 was just 106 million tonnes, marginally better than the level

reached four years ago. The poor performance of DVC and the failure to maintain law and order in the coal mining areas of Bihar and Bengal contributed to the set-back in coal production. At the same time coal could not be transported to thermal stations in adequate quantities because of difficulties in railway movement.

6. In 1979-80 the revenue earning traffic of the Railways in terms of tonnes originating declined by 3.3 per cent from the level reached in 1978-79. The performance of the Railways in terms of tonnes originating of revenue earning traffic has been declining continuously since the peak reached in 1976-77. The deficiencies in the three sectors, power, coal and railways, reinforced one another and inflicted severe damage on the national economy.

7. With the serious deficiencies in infrastructure it was not surprising that there was a fall in the production of major commodities like steel, cement, non-electrical machinery, aluminium and other non ferrous metals and cotton textiles. Sugar production also fell by 28 per cent. There was a decline in capacity utilisation in industry in general.

8. In a situation in which aggregate supply dropped sharply, there was a steep rise in prices. In the fiscal year 1979-80 prices rose by 20 per cent. In some commodities like sugar, gur, khandsari, oilseeds and edible oils the rise was particularly steep. There was also a persistent upward trend in a wide range of manufactures and intermediates owing to the low level of production. The direct and indirect effects of the increases in the prices of crude oil and oil products also contributed to the inflationary pressures in the economy as also the long delayed adjustments in administered prices of commodities like coal and steel. This naturally gave rise to speculative expectations and the liquidity in the system due to large expansion of money supply in the previous years aggravated the price situation.

9. The other area in which there was a deterioration following from all these factors was the balance of payments. It is true that our overall foreign exchange reserves declined by only Rs. 56 crores in 1979-80 but the trend in the various forces operating on the balance of payments has been reversed perceptibly. Export growth in value terms has only been 8 per cent or so which means there was hardly any growth in terms of volume as world inflation has proceeded at about 10 per cent in 1979-80. On the other hand imports have increased by about 25 per cent principally on account of increased oil bill because of a steep rise in the prices of oil and oil products and the consequential impact on other imports such as fertilizer. The result is that the trade gap in 1979-80 was Rs. 2232 crores, double the size of the trade deficit in 1978-79. This has led to a deficit on the current account. The rate of growth of remittances which has in the recent past turned the trade deficit into a surplus on current account also decelerated in 1979-80.

10. Such a dismal economic situation was to a large extent the result of the policies—or should I say lack of policies—of the previous Government. For instance, vacillations in sugar policy contributed to a fall in the area under sugarcane, decline in sugar production and the frittering away of large stocks of sugar carried over from previous seasons through releases which could not be sustained over a period. Had they pursued a more responsible policy on sugar, we would not have been in the unenviable position of having to import sugar for domestic consumption.

11. In infrastructure the lack of coordinated policy in the three sectors of coal, transport and power was responsible for their unsatisfactory performance. The large Budget deficit of Rs. 2700 crores in an economy flush with liquidity and a policy of sweeping taxation on articles of common consumption in a situation of declining production were responsible for the spurt in prices. Finally, the lack of adequate emphasis on export promotion was partially responsible for the reversal of the trend in our balance of payments.

12. What is important now is to devise ways and means to arrest the deterioration and set the economy on the path of stability and growth. The fact that we have a Government which enjoys the confidence of the people and is

decisive should make a qualitative difference; as also the fact that there will be much greater cooperation between the Centre and the States, now that our party has been so enthusiastically returned in the State elections. At the end of May, 1980, we still have food stocks of about 18 million tonnes owing to our earlier foresight. Foreign exchange reserves stood at Rs. 4890 crores as on May 30, 1980. These elements of strength will be effectively utilised to improve the situation. But the House should realise that the magnitude and complexity of the problems we have inherited do not admit of quick and easy solutions. However, the problems are so urgent that we shall tackle them with determination and with the cooperation of all sections of our people.

13. Since it came to power this Government has taken a number of steps to correct the deficiencies in the economic system. Since restoration of infrastructure brooked no delay Government constituted a Cabinet Committee on infrastructure under my Chairmanship to monitor the situation continuously. As power shortages have been an impediment to the growth of production the Committee has devoted a good deal of attention to rectifying the power situation. The Committee wanted to ensure that thermal generation did not suffer for lack of coal and, therefore, decided to make more wagons available for loading coal to thermal stations. As a result the number of wagons loaded daily with coal for thermal stations has gone up from 2900 in January to 3200 in May, 1980.

14. Coastal shipping has been revived to supplement movement of coal by rail and is expected to achieve progressively a target of one lakh tonnes per month to meet the needs of western and southern regions.

15. Due to a number of steps taken coal production increased by 9.4 lakh tonnes in April, and 10.4 lakh tonnes in May, 1980 as compared with April and May, 1979.

16. There has been a dramatic improvement in the port situation. The number of ships waiting for a berth in Bombay, Calcutta and Madras has come down sharply by May, 1980. A good indicator of the improvement in port conditions is the removal of the congestion surcharge for major ports including Bombay and Calcutta from April 1980.

17. As the rainfall during the period October, 1979 to May, 1980 was also deficient causing drought conditions, to continue in many States affecting 220 million population, the present Government, immediately after assuming office, mounted relief operations on a massive scale. Central teams were deputed to these and other States and an allocation of Rs. 150 crores was made for drought relief. More than 10 lakh destitutes were provided free food. In addition, about 65 lakh persons were employed daily under the special Food for Work Programme. Government has decided to continue this programme till the end of September, 1980. The existing subsidy on agricultural inputs, including nitrogenous fertilizers, to small and marginal farmers in the mono-cropped drought affected areas where no rabi crops could be grown has also been extended till the end of March, 1981.

18. A 12-point programme of drought management which provides the basic framework and approach for fighting the drought has been evolved and recommended to the States. A large number of rigs have been deployed for sinking wells and a significant percentage of wells, bored has proved successful. These steps are expected to bring about permanent improvements in availability of drinking water in the drought affected States.

19. The demand for petroleum products, particularly diesel, increased during the last few months owing to a number of circumstances including the drought. The problem was compounded by almost total cessation of supplies from January onwards from the four refineries dependent on Assam crude which between them normally produce around 350,000 tonnes of petroleum products per month. The situation was tackled with the utmost vigour. Firstly, the maximum quantities of diesel and kerosene were imported between January and April, 1980, 6.2 lakh tonnes of kerosene and 1.1 million tonnes of diesel oil were imported as compared with 4.7 lakh tonnes and 4.8 lakh tonnes respectively in January-April

1979. Secondly, the movement of these commodities was speeded up by all available means. The result has been an increase in the level of supplies amounting to 10 per cent compared with the corresponding months in 1979 and avoidance of a possible adverse effect on rabi production due to a diesel shortage.

20. With regard to prices Government has taken a number of important steps. The coverage of the public distribution system has been widened. With regard to edible oils not only has Government undertaken adequate imports but it has also made arrangements to see that a sizeable portion of these imports go into direct consumption. It is hoped that about 3 lakh tonnes of imported oil will go into direct consumption through the public distribution system and cooperatives. In sugar, Government has activated the disrupted dual pricing system.

21. In keeping with our developmental thrust towards the poorest, the banks have been asked to ensure that a significant proportion of the enlarged priority sector credit will flow to the beneficiaries of the 20-Point Economic Programme, which is being revitalised. To further strengthen the linkage between block level development activities and the banks' credit programmes, the banks have been asked to open by the end of the year, branches at all unbanked block headquarters.

22. Hon'ble Members are aware of the critical role played by our exports in our developmental effort. Therefore, the Government had, over the years, endeavoured to provide all facilities and full encouragement to export promotion efforts. The management of credit and investment finance for export promotion in an increasingly competitive international market is, however, becoming more and more complex. There is thus a need for a specialised institution which will become a focal point for all aspects of export credit and which will devote concentrated attention to the needs of the exporting community. Government has, accordingly, decided to set up an Export-Import Bank, to assist the financing of our international trade. We hope this specialised institution will give the desired boost to our export promotion efforts.

23. In the light of the problems currently facing the economy the tasks to be accomplished are clear enough. As there is a great deal of inflationary potential in the economy, the prime objective of our policy will be to achieve price stability. This will have to be done through an increase in aggregate supply and a moderation of aggregate demand. Therefore, we intend to continue our efforts to improve the working of the infrastructure and to augment available facilities with investment wherever necessary. Secondly, the accent will be on utilising existing capacity more effectively, without slackening efforts to increase capacity, to augment supplies of vital commodities like steel, cement, aluminium and fertilizers. This will simultaneously increase production and employment, reduce the need for imports and benefit revenue.

24. With regard to demand management, we shall have to pursue a policy of linking bank credit expansion to productive and priority purposes and check the diversion of funds to speculative ends. We will also have to pursue an interest rate policy which will help in the abatement of inflationary pressures without hurting productive activity. At the same time profiteers and hoarders intent on exploiting current shortages for personal gain will have to be dealt with sternly. Smuggling will have to be countered through Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act and other means.

25. Since there is a great deal of liquidity in the system, there is an obvious need to minimise the growth of money supply by keeping the budget deficit at a much lower level than in 1979-80. This will require a fiscal policy which will reduce wasteful and unnecessary expenditure, invest resources in increasing the economy's production potential and maximise the revenue potential of the existing tax system.

26. In view of the deterioration in our balance of payments we will have to emphasise the promotion of exports to a far greater extent than has been done in the past three years. At the same time, it is necessary to minimise the growth of imports through a much more energetic policy for augmenting domestic production in areas like edible oils, steel, cement, fertilizers, oil and oil products.

27. Government also intends to pursue policies which will encourage savings and investment in the economy. Since 1971, a convertibility clause is being inserted in agreements governing financial assistance to industrial units by public financial institutions. It has been repeatedly represented by industry that the rigours of the convertibility clause are inhibiting investment. Government has carefully considered the matter and has decided that the policy guidelines for insertion of the convertibility clause be modified on the following lines:—

- (a) The mandatory insertion of convertibility clause will in future apply to financial assistance exceeding Rs. 1 crore instead of Rs. 50 lakhs prescribed at present.
- (b) The financial institutions should hereafter exercise the conversion option in such a way that they do not acquire more than 40 per cent of the share capital of an existing concern. However, in case of persistent default in repayment of loans or mismanagement of an assisted company or continuous closure of an industrial unit of a company producing goods and services essential to the community, the financial institutions might, with the concurrence of Government, exercise their conversion option in such a way that their share-holding can go up to 51 per cent or above.
- (c) Under the existing soft loan scheme for modernisation of jute, cotton textiles, cement, sugar and certain engineering industries, no convertibility clause is being inserted at present. This exemption is being extended to assistance for modernisation in any industry and for rehabilitation of sick units.

Government hopes that these policy changes would remove the present inhibition and encourage fresh investment in and modernisation of industry.

THE PLAN AND BUDGET ESTIMATES FOR 1980-81

28. In our preoccupation with the immediate problems of economic management we should not lose sight of the need to build up the growth potential of the economy over the medium term. If we do not do so, the short term difficulties will only grow further. The reconstituted Planning Commission will present the new programmes and priorities when the Plan is formulated by the end of this year. But meanwhile a Plan for the year 1980-81 has been formulated which will be dovetailed into the Sixth Plan later. The broad objective of the Plan would be to achieve a higher growth rate of 5 per cent per annum.

29. The annual Plan for 1980-81 seeks to revive and restore the health of the economy and accelerate the pace of growth and employment generation. Though the priorities laid down by the earlier Government are not acceptable to us, we have recognised that on-going projects should be fully provided for. Within the room for manoeuvrability permitted by this consideration, we have effected changes in plan provisions or provided for new programmes so as to give a reorientation to the Plan in the desired direction.

30. The new Planning Commission has made a quick review of Plan programmes and priorities. I am glad to announce that in the light of this review the annual Plan outlay for 1980-81 of the Centre is being raised to Rs. 7,340 crores, an increase of Rs. 767 crores over the outlay in the interim Budget; compared with last year's original outlay it is higher by 14.5 per cent. It will be financed by a budgetary provision of Rs. 5,322 crores and internal and other resources of public sector undertakings of Rs. 2,018 crores. A provision of Rs. 3,094 crores has been made for central assistance to the outlay on States' Plans, Union territories' Plans and sub-plans of hills and tribal areas, special component plans for the scheduled castes, schemes of the North Eastern Council, Rural Electrification Corporation and natural calamities. Inclusive of their own resources their Plan outlay will be Rs. 7,253 crores as against an outlay of Rs. 6,099 crores in 1979-80. Altogether the total Plan outlay of the Centre, States, Union territories, schemes of North Eastern Council etc., would amount to Rs. 14,593 crores in 1980-81 as compared with Rs. 12,511 crores in 1979-80—a step up of 16.6 per cent.

31. It is this Government's firm belief that economic growth could be accelerated and its fruits widely shared only if employment opportunities in rural areas are significantly augmented. Development will have no meaning to the vast majority of our people if the poor in the rural areas are not able to secure a livelihood through satisfactory productive work. As an integral part of the new Plan, we have therefore, decided to launch a massive National Rural Employment Programme based on a strategy which will seek to blend opportunities for self-help and optimum utilisation of available local resources. Such a programme will go a long way towards revitalising the rural economy and developing the infrastructure facilities so essential to the life of the community.

32. The Food for Work Programme initiated by us in 1977 has an important part to play in this regard. But in the last two years this programme has displayed certain cardinal weaknesses. In many cases, no attempts have been made to develop an inventory of projects which will meet not only the local needs but also fit in with the overall national priorities.

There was also no firm indication of annual allocation of foodgrains. The programme thus in effect continued on an ad hoc basis. No arrangements were also made for financing the cash component of the works programme undertaken by the State Governments with the help of foodgrains allocated to them. The result was that they could not undertake works which could have led to the creation of durable assets and the building up of productive potential of the areas concerned.

33. In the new National Rural Employment Programme, States will receive assistance not only in the form of foodgrains but also cash assistance so as to enable them to undertake truly productive works of lasting benefit. The Budget estimates which have been presented to the House provide Rs. 340 crores in 1980-81 for this programme. It is estimated that the programme, if properly implemented, could generate 850 to 900 million man days of additional employment. Some part of the provision for this scheme would be specifically earmarked for high priority programmes like social forestry, fuel plantation, rural community housing and water supply and nutrition. Rs. 10 crores have been provided for the Food for Nutrition Programme.

34. The process of economic growth will be incomplete unless the benefits of such growth reach the weakest sections of society. Therefore, the improvement of the socio-economic conditions of the scheduled castes should be a major element of our strategy of development. Comprehensive special component plans for the scheduled castes will have to be drawn up with the objective of earmarking outlays in all relevant sectors in proportion to the scheduled caste population in each State. Such outlays are to be utilised for helping the scheduled caste families to acquire income generating assets and relevant skills for the betterment of their living conditions. The Budget breaks new ground by providing for a special central assistance of Rs. 100 crores to the States to act as a catalyst in the generation of more funds from other sources including financial institutions. This will enable the authorities to provide as a package all the inputs needed in an integrated programme of promotions of the socio-economic condition of scheduled castes.

35. A provision for Central assistance of Rs. 70 crores has been made for the development of tribal people and areas under the Tribal sub-plan. Additional pockets with a population of 10,000 and having at least 50 per cent tribal concentration will be identified, thus bringing nearly 75 per cent of the tribal population in eighteen States and Union territories within the Tribal sub-plan. Greater emphasis will be laid on selected programmes which can benefit the tribal families.

36. A provision of about Rs. 50 crores has been made in the annual Plan for 1980-81 for providing house sites for the landless and weaker sections as part of the 20-Point Economic Programme. The Rural Housing-cum-Hut Construction Scheme for landless workers being operated under the revised Minimum Needs Programme provides not only house sites but also assistance for the construction of huts. This provision will be supplemented under the National Rural Employment Programme which will cover community housing projects in rural areas. Nearly 8 lakh landless families are expected to benefit under this scheme.

37. Since India lives in its villages and nearly 70 per cent of its population derives its livelihood from agriculture the prosperity of the country depends upon the modernisation of agriculture. The year 1979-80 is a grim reminder of the importance of the performance of agriculture to the development of the Indian economy. The Plan outlay on agriculture and rural development in the current year is being increased to Rs. 2,247 crores from Rs. 1,811 crores in 1979-80. This includes the provision in the Central Plan of Rs. 158 crores for Small Farmers Development Agency, Drought Prone Areas Programme, Integrated Rural Development Programme etc.; Rs. 32 crores for better exploitation of inland and marine fish potential; Rs. 54 crores for Operation Flood II Project; Rs. 59 crores for schemes of agricultural research and education oriented towards improving agricultural productivity through better seeds, better agronomic practices, better water management and better use of fertilizers and other essential inputs; and Rs. 10 crores to increase the production of oilseeds to reach a target of 12 million tonnes.

38. The current levels of international prices of oil and oil products have highlighted the importance of other fuels. Forests can play an important part in providing one such fuel. As forests in India have suffered fast destruction by people in their search for fuel, it is essential that people's participation in the development of forest is secured on an urgent basis. Social forestry in villages will besides meeting the energy requirements of the people also provide additional employment. The raising of fuel and fodder is proposed to be made a part of Minimum Needs Programme and it will receive high priority in the National Rural Employment Programme.

39. We have to press on with the task of increasing the area under irrigation to avoid fluctuations in production and to increase productivity. Therefore, the outlay on major and medium irrigation projects including flood control for 1980-81 is being stepped up to Rs. 1,380 crores from Rs. 1,258 crores last year. The minor irrigation programme would continue to receive special attention and an outlay of Rs. 266 crores has been made for this purpose. This provision will be supplemented by large financial support from the Agricultural Refinance and Development Corporation. The additional irrigation potential resulting from all this expenditure is expected to be 2.5 million hectares.

40. Clean and safe drinking water is essential for improvement of the quality of life in rural areas. The Central Plan for 1980-81 provides an outlay of Rs. 100 crores as against Rs. 80 crores in 1979-80. Inclusive of the provisions in the States' Plans, a total sum of Rs. 294 crores will be available for this vital programme. It is expected that by the end of the current year, 35,000 additional villages identified as problem villages will be having protected water supply arrangements. A part of the outlay has been earmarked for rigs to be supplied to States for boring wells in drought affected areas. An additional sum of about Rs. 40 crores has been allocated in the current year to the drought affected States to take up new water supply schemes and complete those already in hand.

41. The khadi, village and small scale industries sector has the highest employment potential next to agriculture. The outlay on this sector in the current year will be Rs. 150 crores and additional production during the year is estimated at Rs. 146 crores. The House will recall that the 20-Point Economic Programme has particularly emphasised the development of the handloom sector in this context. In pursuance of this objective, we propose to set up a national level Handloom Development Corporation for providing a package of marketing and developmental assistance for the handloom industry. Provision has also been made for establishing an Institute of Handloom Technology in the North-Eastern region, which is well known for its exquisite handloom products.

42. The provision for the power sector has been raised by over 11 per cent i.e., from Rs. 2,466 crores in 1979-80 to Rs. 2,745 crores. The work on the four Super thermal power stations in the different regions of the country is being accelerated. Total outlay on the rural electrification programme will be Rs. 285 crores in 1980-81. The target in 1980-81 is the energisation of 4 lakh pumpsets and the electrification of 25,000 villages.

311 GI/80—3

43. Similarly, an outlay of Rs. 473 crores is being provided in 1980-81 as against Rs. 364 crores last year for improving the production of coal (including lignite). This includes a provision of Rs. 92 crores for the Neyveli Lignite Corporation. The bulk of this allocation is for the second mine project which will produce 4.5 million tonnes per annum and the second thermal power station with a generating capacity of 630 MW. A production target of 113.5 million tonnes has been set for coal for the current year as against the actual production of 106 million tonnes in 1979-80.

44. In view of the impact on the balance of payments of the rising prices of oil there can be no two opinions about the urgency of developing our own oil resources. The Plan outlay for the petroleum sector for 1980-81 is Rs. 837 crores, Rs. 215 crores more than the outlay last year. The Budget provides only Rs. 99 crores out of this. This outlay is for the completion of facilities for Phase III development of Bombay High and advance action in regard to Phase IV so as to build up a production capacity of 12 million tonnes per year. It also includes the expenditure required for the development of the South Bassein Gas field and the gas pipeline to the new fertilizer projects. On-shore exploratory drilling in the eastern region is to be intensified in view of the region's higher potential for hydro carbon discoveries.

45. The Central Plan outlay on chemicals and fertilizers is being raised to Rs. 319 crores in 1980-81 to provide adequately for new gas-based fertilizer plants in Maharashtra and Assam. In addition, a provision of Rs. 20 crores has been made for fertilizer projects in the cooperative sector.

46. The Central Plan also provides in the current year an outlay of Rs. 803 crores for the steel sector as against Rs. 600 crores last year. The outlay includes a provision of Rs. 200 crores for raising the capacity of the Bokaro Steel Plant to four million tonnes per annum and an outlay of Rs. 190 crores for the Bhilai Steel Plant for a similar expansion. Work on the Salem Project will proceed at the required pace with an outlay of Rs. 57 crores. A substantial beginning will be made on the new Visakhapatnam Steel Plant with a provision of Rs. 70 crores. The target of saleable steel in the current year has been fixed at 8.76 million tonnes as against the anticipated production of 7.22 million tonnes in 1979-80.

47. An outlay of Rs. 130 crores is being made in 1980-81 for the mines sector. This includes a provision of Rs. 10 crores for the new east coast aluminium project, Rs. 28 crores for the Malankhand Copper Project and Rs. 19 crores for the intensification of the activities of the Geological Survey of India and the Mineral Exploration Corporation.

48. A provision of Rs. 64 crores has been made for BHEL for its continuing schemes and for the production of large size turbo generators at Harwar and the expansion of boiler manufacturing capacity at Tiruchy.

49. Since port congestion also has figured prominently as a constraint till recently, a provision of Rs. 102 crores is being made in 1980-81 for developing major and minor ports. However, only a sum of Rs. 60 crores has been provided in the Budget as the rest of the expenditure is being met from internal resources of the Port Trusts. Bombay, Madras and Cochin are being equipped to handle the anticipated increase in container traffic. A beginning has been made on the integrated development of Cochin port.

50. The Plan outlay for 1980-81 for the Posts & Telegraphs Department is Rs. 415 crores. It is proposed to provide additional 1.75 lakh lines switching capacity and 1.7 lakh direct exchange lines and other facilities. The number of post offices in rural, backward and hilly areas is also proposed to be increased. The norms for providing telegraph and telephone facilities in tribal areas have been further liberalised to cover areas having a population of 2500 in a group of villages within a radius of 10 kms. Provision has also been made for the expansion of manufacturing capacity for switching equipment.

51. Family Planning programme suffered a serious set back in the past three years. A revitalisation of this programme must constitute an important element of the new Five Year Plan, if an improvement of the living conditions of our people is our goal. A provision of Rs. 250 crores is being made in 1980-81 for health and family welfare. Of this Rs. 140

crores will be for family welfare. The emphasis in the family welfare programme will be on educating the people about the desirability of a small family and providing the necessary technical services on an adequate scale. An attempt will also be made to provide improved health services in rural areas, eradicate communicable diseases and provide health education.

52. The development problems of a poor society of 650 million people are bound to be spendous. For a solution of these, within a reasonable time, it will be necessary to harness the forces of science and technology. India is favourably placed with regard to the development of science and technology in that she has a large pool of scientific and technical man-power and a vast institutional infrastructure developed over the last thirty years. While our scientific institutions can help to advance the frontiers of knowledge, it is science based technology which can help to raise production and productivity. Therefore, an outlay of Rs. 116 crores has been provided in the Central Plan for 1980-81 for science and technology.

53. I will now make a brief mention of a few changes in the non-Plan expenditure. The provision for Defence expenditure is Rs. 3600 crores, Rs. 300 crores more than the provision made in the Interim Budget. The provision for export subsidy has been increased from Rs. 330 crores to Rs. 355 crores, in view of the need for a larger export effort.

54. Loans to State Governments, as their share of small savings collections, are being stepped up from Rs. 650 crores in the interim Budget to Rs. 715 crores, in view of the anticipated improvement in these collections. Short term loans to State Governments for agricultural inputs are also being increased by Rs. 50 crores. Besides additional provision has been become necessary to meet unavoidable commitments like additional dearness allowance to Central Government employees, purchase of heavy water for atomic power plants, etc. However, the above increase in non-plan expenditure will be partially offset by reduction in fertilizer subsidy.

55. The Constitution envisages provision of free legal aid by Government in order to ensure that an opportunity for securing justice is not denied to any citizen because of economic or other disabilities. The concept of legal aid has also been dealt with by a Committee on Juridicare headed by Justice P. N. Bhagwati, whose Report dated 31st August, 1977 has been laid before Parliament. Several States have been attempting legal aid programmes. It is proposed to co-ordinate these schemes and also initiate suitable schemes at the Centre after an examination of the various aspects. A committee for guiding the legal aid schemes and implementing the same is being constituted with a Supreme Court Judge as its Chairman. The Budget for 1980-81 makes a provision for this purpose.

56. Taking into account the effect of the above and some other changes, the total non-Plan expenditure is now estimated at Rs. 13,051 crores as against Rs. 12,822 crores in the interim Budget.

57. As regards receipts in the current year, at existing levels of taxation Corporation tax is estimated to yield Rs. 11 crore more than what was reflected in the interim Budget; this improvement is mainly based on the actual trends of collection in 1979-80. On the basis of latest available data on estimated levels of imports and production during the current year, Customs duties and Union Excise duties are also expected to yield Rs. 40 crores and Rs. 108 crores respectively more than anticipated in the interim Budget. However, these increases will be more or less offset by the recent decision of Government to withdraw customs and excise duties on fertilizers. Taking into account States' share of taxes net tax revenue at existing rates of taxation is estimated at Rs. 8723 crores as against Rs. 8725 crores in the interim Budget.

58. On the basis of the latest indications available external assistance, net of repayments, in 1980-81 is estimated at Rs. 1252 crores showing an increase of Rs. 56 crores over the figures included in the interim Budget. In addition we expect to avail of a loan of Rs. 540 crores from the Trust Fund of the International Monetary Fund in 1980-81 and the Budget assumes credit for this.

59. There is a welcome increase in small savings collections. The estimate for 1980-81 is now placed at Rs. 1100 crores as against Rs. 1000 crores in the Interim Budget. Of the in-

crease of Rs. 100 crores, i.e. 65 crores will accrue to the States as their share.

60. It has been decided that a part of the investible resources of Life Insurance Corporation, General Insurance Corporation, and Unit Trust of India should be lodged with Government in Special deposit accounts to augment resources for financing the Plan. Budget for 1980-81 takes a credit of Rs. 100 crores on account of these deposits.

61. When we are seeking to step up investment in public sector, it is necessary to adopt an innovative approach to the problem of mobilising resources for sustaining such investment. As Hon'ble Members know, private sector companies raise resources in the form of deposits from the public. Government feels that there is no reason why public sector companies with competent professional management should not do so. Accordingly, we have decided to allow selected public sector units to raise public deposits on the same lines as the companies in the private sector. When this scheme makes headway, dependence of these public sector enterprises on budgetary support will get reduced. But I have refrained from taking credit for such relief at this stage.

62. Taking into account other variations and also the effect of the changes in the fare and freight rates of Railways and of changes in Posts and Telegraphs tariff, to which I will refer a little later, the total receipts in 1980-81 are estimated at Rs. 19,827 crores as against Rs. 18,980 crores in the interim Budget. Total expenditure is estimated at Rs. 21,467 crores. The deficit at existing rates of taxes will thus be Rs. 1640 crores.

PART B

63. I now turn to my proposals in the field of direct taxes. In framing these proposals, I have borne in mind certain broad considerations, namely, that the rates of direct taxes should be such as to promote voluntary compliance; that the farmers, workers and the middle class should be afforded some relief in pursuance of the commitment in our Party's manifesto and some stimulus should be provided for raising the level of savings and investment in the national economy. At the same time, a concerted attempt should be made to counter certain widely prevalent devices for tax avoidance through fragmentation of income and wealth.

64. The middle class is among the worst hit by the rise in prices in recent years. As Hon'ble Members are aware, even skilled workers in the organised sector are now liable to income-tax, at the present level of exemption. In order to afford a measure of relief to this class of persons, I propose to raise the exemption limit for income-tax on personal incomes from Rs. 10,000 to Rs. 12,000. With a view to keeping the sacrifice of revenue within manageable limits, the nil rate slab of income is being retained at Rs. 8,000. As a result, in cases where the taxable income exceeds Rs. 12,000, the incidence of income-tax, excluding surcharge, will remain at the existing levels, subject to the grant of marginal relief in cases where the taxable income exceeds the exemption limit by a small margin. This proposal will benefit more than six lakhs of income-tax payers.

65. Hon'ble Members will recall that the rates of income-tax on the personal incomes were reduced in 1974 on the basis of a recommendation of the Direct Taxes Enquiry Committee and this process was taken one step further in 1976 when these rates were again lowered. The reduction in rates had largely fulfilled the expectation that it would lead to better tax compliance. Unfortunately, the movement in this direction was reversed under the Janata Government and the rates of income-tax were increased in stages. I am of the view that the position in this regard should be set right. I accordingly propose to reduce the surcharge on personal incomes in the case of all categories of non-corporate taxpayers from 20 per cent to 10 per cent. This will not only bring down the maximum marginal rate of tax from 72 per cent to 66 per cent but will benefit taxpayers in all slabs of income.

66. In view of the somewhat steep rise in prices of assets, I also propose to raise the exemption limit for wealth-tax from Rs. 1 lakh to Rs. 1.5 lakhs with effect from the current assessment year. In cases where the taxable wealth exceeds this limit, the tax burden will, however, be retained at existing levels, subject to the usual marginal relief.

67. Government hopes that these concessions will provide the necessary inducement to the vast majority of our taxpayers for correct declaration of their incomes and wealth.

68. I propose to counter some of the more commonly used devices for tax avoidance.

69. As Hon'ble Members are aware, the separate treatment accorded to Hindu undivided family in tax laws has been widely used for avoidance of proper tax liability. I accordingly propose to de-recognise partial partitions of Hindu undivided families both for income and wealth taxation. Partial partitions made on or after 1st January, 1979 will not be recognised for tax purposes and taxes will continue to be levied on the basis that the existing Hindu undivided family had continued to remain joint.

70. At present, Hindu undivided families having one or more members with independent income exceeding the exemption limit are charged to income-tax at rates which are somewhat higher than those applicable in the case of individuals. In order to further restrict the use of Hindu undivided family for the purposes of tax avoidance, I propose to raise the rates of income-tax in the case of such Hindu undivided families. The maximum marginal rate of 66 per cent will now apply on the slab of income over Rs. 50,000 and the rates on some of the lower slabs will also be raised to somewhat higher levels. With these two changes in regard to tax treatment of Hindu undivided families, I hope that the urge for forming multiple Hindu undivided families merely for fragmentation of income and reduction of tax liability will be weakened.

71. Hon'ble Members will recall that the Government had in 1970 taken several measures to prevent the use of private discretionary trusts as a device for tax avoidance. Experience, however, shows that these measures have not been fully effective and the proliferation of such trusts has not been curbed to the desired extent. I, therefore, propose to tighten the provisions in respect of private trusts. At present, discretionary trusts are taxed at a flat rate of 65 per cent of their income and 1.5 per cent of their wealth, or at the rates applicable in the case of an individual, whichever is higher. Under my proposal, such trusts will be charged to income-tax at the maximum marginal rate and to wealth-tax at the flat rate of 3 per cent or at the appropriate rate applicable in the case of an individual, whichever is higher. I also propose to make several other provisions in relation to taxation of private trusts with a view to plugging some loopholes which have come to the notice of Government. All these provisions will take effect from the current assessment year.

72. Charitable and religious trusts are sometimes used for acquiring or maintaining control over business or industry for private ends. In 1975, we had laid down a pattern for investment of funds of charitable or religious trusts if they were to continue to enjoy the tax exemption. With a view to enabling such trusts to change over to the new pattern of investment in a smooth and gradual manner, the law provided that the new pattern may be adopted before 1st April, 1978. This date was subsequently extended to 1st April, 1981. Such trusts have, therefore, been given ample time to adjust to the new policy. I want to put them on notice that this time limit will not be extended.

73. Our tax laws have always sought to encourage long-term savings through life insurance, provident funds and other similar instruments. Unfortunately, the efficacy of the provisions for encouraging savings was impaired last year when the incentives for savings were drastically reduced. Hon'ble Members should be glad to know that I propose to restore incentives for such savings to the pre-1979 budget levels. The taxpayers will thus be entitled to 100 per cent deduction in respect of the first five thousand rupees of the qualifying savings, 50 per cent in respect of the next five thousand rupees and 40 per cent of the balance.

74. As a further measure for promoting savings in the household sector, I propose to give an option to income-tax payers to retain moneys in their Compulsory Deposit Accounts beyond the due dates on payment of interest at the existing rate applicable to such deposits. Further, I propose to liberalise the tax exemption in respect of interest on balances with recognised provident funds. At present, interest on such funds is exempt from income-tax to the extent it does not

exceed one-third of the salary income of the employee. I propose to remove this ceiling limit.

75. It is essential to promote new investment in industry. At the same time, the fiscal system should not lead to a bias in favour of capital-intensive techniques. Keeping these twin objectives in view, I propose to continue the tax holiday in respect of new industrial undertakings, ships and hotels, but in a modified form. Under my proposal, tax holiday will be available in respect of new industrial undertakings, ships or approved hotels with reference to a specified percentage of the income derived from these sources. In the case of companies, 25 per cent of the profits derived from these sources will be exempt for a period of seven years. In the case of noncorporate taxpayers, the percentage of exempted profits will be 20 per cent. In the case of co-operative societies, the tax holiday will be available for a period of ten years as against seven years in the case of other categories of taxpayers. This concession will be available in the case of all small-scale industrial undertakings which go into production after 31st March, 1981 but before 1st April, 1985, that is, till the end of the new Five-Year Plan period. For other industrial undertakings, the concession will apply only where they do not produce articles or things listed in the Eleventh Schedule to the Income-tax Act. The concession will also be available in the case of approved hotels which start functioning or new ships which are acquired during that period.

76. It is necessary to encourage new investment particularly in view of shortages in several key sectors of the economy. As a special stimulus for new investment, I propose to allow, in the year of installation, an additional depreciation in an amount equal to 50 per cent of the normal depreciation on new machinery or plant installed during the new Plan period. The proposed additional depreciation will not be admissible in respect of ships, aircraft, road transport vehicles, office appliances or machinery or plant installed in office premises or residential accommodation.

77. There is a widespread feeling of frustration among the scientific community. This Government is keenly aware of the contribution which our scientists and technologists can make to the economic regeneration of India and is determined to promote research and development activities in a big way. I, therefore, propose to allow a weighted deduction in an amount equal to 125 per cent of the actual expenditure incurred on scientific research in any in-house R&D facility where such expenditure is incurred on a programme approved by the prescribed authority having regard to the social, economic and industrial needs of India. In addition, I propose to extend the scope of the existing provision for a weighted deduction on the expenditure incurred on scientific research under sponsored programmes in approved laboratories so as to cover the expenditure similarly incurred in in-house R&D facilities of public sector companies. I have no doubt that the Hon'ble Members will welcome these concessions.

78. At present, income-tax payers are required to pay advance tax during the financial year on the basis of their own statements or estimates. Where the estimated advance tax is likely to fall short of the tax on current income by more than 33-1/3 per cent of the estimate, the taxpayers are required to make an upward revision of the estimates. I propose to reduce this margin from 33-1/3 per cent to 20 per cent in the case of companies. There will be no change for other taxpayers. This change will enable us to realise a larger share of the tax due as advance tax and thus have a favourable impact on Government's ways and means position in 1980-81.

79. In order to encourage the employment of blind and handicapped persons in business and industry, I propose to provide for a weighted deduction of one and one-third times the salary paid to such persons by employers where such salary does not exceed twenty thousand rupees in a year. Further, I propose to enhance the deduction currently available in computing the taxable income of blind and handicapped persons from five thousand rupees to ten thousand rupees.

80. At present, standard deduction in computing the salary income is not available in the case of pensioners. With a view to affording some relief to pensioners who are amongst

the worst hit by the rise in price, I propose to extend the benefit of standard deduction in their case as well.

81. In order to encourage our sportsmen to compete in international events, I propose to allow a deduction equal to 25 per cent of their foreign earnings if these are brought into India in foreign exchange. This provision will apply in relation to the current assessment year and onwards. I also propose to allow higher deduction in respect of savings made by sportsmen through life insurance and provident funds etc. as currently available in the case of authors, playwrights, artistes, musicians and actors, sportsmen will thus be entitled to deduct contributions made to life insurance and provident funds up to 40 per cent of their professional income and 30 per cent of the remaining income, subject to a maximum of Rs. 50,000.

82. In 1978, certain restrictions were placed on the deductible amount of expenditure on advertisement, publicity and sales promotion. These restrictions have particularly hurt small and medium business. I, therefore, propose to do away with these restrictions.

83. At present, income from poultry and dairy farming and livestock breeding is exempt from income-tax upto 33-1/3 per cent of such income or ten thousand rupees, whichever is higher. I feel that time has come when persons deriving income from these sources should also contribute a little more to the national exchequer. I accordingly propose to restrict the deduction in respect of such income to one-third of such income or fifteen thousand rupees, whichever is less.

84. At present, agricultural property is included in the taxable wealth for the purposes of the levy of wealth-tax. At the time when agricultural property was brought within the tax net, it was hoped that it would be a potent instrument for mobilising resources from the affluent section of agriculturists. But our experience of over the last decade has been most disappointing. The amount realised as wealth-tax on agricultural property has generally been less than Rs. 1 crore per annum. The valuation of agricultural land has posed difficulties leading to complaints of harassment. As this tax has clearly failed to achieve its original objective, I propose to discontinue the levy of wealth-tax on agricultural property except in the case of owners of tea, coffee, rubber and cardamom plantations. I am sure that this measure will be widely welcomed by our farmers.

85. I also propose to make certain amendments in the Income-tax Act to counteract certain court decisions which have resulted in unintended benefit to taxpayers. The Finance Bill further contains certain proposals for the amendment of direct taxes which are of minor significance. I will not take the valuable time of the House in explaining the same.

86. The reduction in rates and other concessions in respect of direct taxes should ordinarily involve loss of revenue. However, I am of the view that reduction in rates will lead to significantly improved compliance with tax laws. The legislative amendments made for countering tax avoidance devices and the changes in the provisions in regard to advance tax should result in larger accretion of revenue. On a broad judgement of the overall impact of all the proposals relating to income-tax and wealth-tax, I am not assuming any loss of revenue. I recognise, however, that there may be need for some adjustment in the inter-se shares of Centre and States under Income-tax. Such adjustments will be made in the course of the year in the light of trends in collections.

87. An upward adjustment of lending rates should moderate the inflationary pressures in the economy. I accordingly propose to revive interest-tax in relation to interest earned by scheduled commercial banks after 30th June, 1980. The scope of the levy is being extended to cover also interest received by the larger all-India industrial finance institutions, namely, IDBI, ICICI, IFCI, and IRCI. The tax will be levied at the rate of 7 per cent on the chargeable amount of interest as in the past. This measure will yield Rs. 217 crores in a full year and about Rs. 108.5 crores in the year 1980-81.

88. With a view to checking lavish expenditure incurred on accommodation and entertainment in luxury hotels, I propose to introduce a Bill in the current session to levy a new tax at 15 per cent on gross receipts of hotels in which the minimum tariff for a single room is 75 rupees per day. The new levy is proposed to be made effective from 1st September,

1980. This will yield about Rs. 12 crores in a full year and the revenue during 1980-81 will be of the order of crores.

89. I shall now turn to my proposals on indirect taxes. In framing my proposals I have kept in view the following objectives. To the extent additional resource mobilization is inescapable, this should be done in such a way as not to enhance the burden on any commodity significantly. Subject to this consideration, the small scale segment of our industry should be encouraged. Industries with significant employment and export potential should be provided encouragement through suitable adjustment of duty structure. The duty burden on some articles of common consumption should be reduced or totally removed.

90. At the outset I would like to put the Hon'ble Members at ease by pointing out that my proposals are modest. I have tried to avoid the usual device of picking out selected items for new or increased levies at relatively high rates.

91. For this year, I have sought to spread the effect of the additional taxation thinly on a wide range of products, taking care to leave out articles of common consumption. I propose to achieve this objective through the special excise duty which is even now leviable on all excisable goods at 1/20th of the basic excise duty, but from which a number of commodities have been exempted. Under my proposal, the special excise duty will be levied on those items which are at present, exempt from the levy, at the rate of 1/20th of the effective basic excise duty rates applicable. Certain commodities will, however, continue to be totally exempt from the levy. Thus there will be no special duty on motor spirit including naphtha, kerosene, high speed diesel oil, light diesel oil and liquefied petroleum gas or on coal or electricity. Again, the special excise duty will not be levied on matches, or on vanaspati, or on goods falling under Tariff Item 68. Where special excise is already leviable at 1/20th of the effective basic duty, I propose to increase this to 1/10th of the effective basic duty. This increase will not, however, apply to furnace oil, asphalt, bitumen and tar, petroleum products not otherwise specified and calcined petroleum coke. Sugar and processed vegetable non-essential oils will also not be subjected to the increased levy. Cigarettes, which are at present totally exempt from special excise duty will be subjected to special excise duty at 1/10th of the basic excise duty rates. These proposals would yield a revenue of Rs. 197.71 crores in a full year. The impact of these proposals relating to special excise duties will also yield a sum of Rs. 16.75 crores in the shape of countervailing duties on imported goods.

92. Soda ash and caustic soda command a sizable premium in the market on account of persistent shortages. I propose to mop up a part of this premium by raising the excise duty on these products from 10 per cent to 15 per cent ad valorem. I also propose to increase the excise duty on starch from 10 per cent to 15 per cent ad valorem. This step will bring these chemical products on a par with other chemical products which, in general, bear excise duty at 15 per cent ad valorem. Synthetic rubber at present bears duty at the very low level of 5 per cent ad valorem. As a revenue measure, I propose to raise the excise duty on synthetic rubber from 5 per cent to 10 per cent ad valorem. Similarly, the rate of excise duty on specified acids is being raised from 10 per cent to 15 per cent ad valorem. These measures would fetch in a full year, additional revenue of Rs. 18.93 crores.

93. On revenue considerations, I propose to subject molasses to a specific duty of Rs. 30 per metric tonne under a separate item in the Central Excise Tariff instead of 8 per cent under Item 68 of the Central Excise Tariff as at present. The levy is, however, proposed to be restricted to molasses produced in vacuum pan sugar factories. Molasses produced in khandari sugar units, which goes inter alia, for edible purposes, is proposed to be exempted. The revenue yield as a result of this proposal is estimated to be Rs. 4.24 crores in a year.

94. I now come to proposals which are designed to provide a higher degree of protection to certain sectors of indigenous industry. The first proposal relates to audio frequency amplifiers, an item reserved for the small scale sector. In view of the adverse effect of imports of this item, I propose to increase the customs duty on imports from 75 per cent to 120 per cent ad valorem. My other proposal relates to imported unexposed colour positive cinematograph films, in respect of which the basic customs duty is proposed to be raised from 50 paise to Re. 1 per linear metre to enable the indigenous

public sector unit to withstand competition from imports. I also propose to increase the countervailing duty on imported computers from 10 per cent to 20 per cent ad valorem as a measure of affording protection to the indigenous computer industry. These measures are designed to yield additional revenue of about Rs. 1.83 crores in a full year.

95. I have only one more revenue proposal in the field of indirect taxes. This relates to passengers' baggage. As Hon'ble Members are aware, baggage allowances were substantially liberalised in 1978 and, for the generality of Indian passengers, going abroad for short visits, the allowances consist of Rs. 1,000 worth of duty-free goods and Rs. 2,000 worth of goods on payment of duty. Despite this liberalisation, goods in the nature of baggage continue to be imported by many passengers in quantities substantially higher than the permissible limits. This is mainly due to the prevailing craze for foreign goods and the high margin of profit on the sale of these goods in India. Such cases of import of baggage items in excess of the permissible limits necessitate initiation of adjudication proceedings which generally have the effect of slowing down the tempo of passenger clearance in our international airports. I have given thought to this problem and I am making two proposals in this regard. The first is a pure revenue measure of increasing the effective rate of duty on baggage articles in excess of the free allowances from 120 per cent ad valorem to 150 per cent ad valorem. This measure is to come into force immediately and is expected to yield an additional Rs. 20 crores in a full year. The second measure to be brought into force shortly, provides for the levy of duty at a flat rate of 320 per cent on baggage imported in excess of the permissible limits, that is, in excess of what can be passed free or on a duty of 150 per cent. At present, such articles would be treated as unlicensed imports, resulting in confiscations, fines and penalties designed to wipe out any profit on their sale. The increased rate of duty is intended to replace these fines and penalties, without having to go through the time-consuming process of adjudication. Goods which are obviously in the nature of trade goods will, however, still attract penal action.

96. I have a few other proposals which are essentially in the nature of rationalisation measures. The first one relates to aerated waters. In the interest of simplification, it is proposed to do away with the existing distinction between aerated waters containing caffeine and those not containing caffeine for the purpose of excise duty. Instead, it is proposed to levy on all flavoured aerated waters a uniform duty at 40 per cent ad valorem. The revenue effect of the proposal is expected to be negligible.

97. I have given considerable thought to the problems thrown up as a result of the changes made in the 1979 Budget in the excise duty structure applicable to the match industry. While the duty advantage enjoyed by the cottage sector obviously needs to be maintained, the non-mechanised middle sector should not be allowed to make inroads into the cottage sector. In order to ensure that the benefit of the lower rate of duty accrues only to the genuine cottage sector units, I propose to confine the duty concession to match boxes bearing approved labels and sold to or marketed through the KVIC, State Agencies and registered cooperative societies. At the same time, I do not find justification for the continuance of the existing limits placed on the clearances of matches by the cottage sector at the concessional rate of duty. I, therefore, propose to abolish the existing limit on production by the cottage sector units. I am confident that this package of measures will result in accelerated growth of the cottage sector of the match industry.

98. There have been complaints of malpractices in the biri industry by manufacturers who have been taking advantage of the liberal exemption limit applicable to the unbranded sector which is at present 60 lakhs of biris per manufacturer per year. With a view to reducing the possibilities of malpractices, I propose to lower this exemption limit to 30 lakhs of unbranded biris per manufacturer per year, which will still leave out of the excise net the really small manufacturer and the self employed manufacturer. This is not designed as a revenue measure.

99. Some of the provisions in the Finance Bill are aimed at rationalisation or clearer definition of certain central excise tariff items to remove doubts or difficulties which have come to notice. The details of these measures may be found in the Budget papers.

100. I shall now turn to concessions in the area of indirect taxes. The small manufacturer plays a significant role in our economy. I would like to improve his competitive position vis-a-vis the large manufacturer and thus widen the entrepreneurial base of our economy. Only in this way can we check concentration of economic power. There is already a scheme of excise duty concessions applicable to manufacturers of 70 excisable commodities, under which clearances upto Rs. 5 lakhs in value in a year have been exempted from duty. I now propose to liberalise this concession in two respects. First I propose to include two more groups of commodities under the scheme. These are chemicals, namely, sodium bichromate, bleaching powder, calcium carbide and artificial and synthetic resins and plastic materials. Besides, the coverage is being widened in respect of paper and paper boards. But the second and more important concession which I propose to introduce is that in respect of all the commodities covered by the scheme, clearances between Rs. 5 lakhs and Rs. 15 lakhs will bear only three-fourths of the applicable rate of excise duty as against the normal duty at present. This measure should benefit a large number of small manufacturers. The revenue sacrifice will be of the order of Rs. 6.50 crores in a full year.

101. Last year's Budget made a change which affected a substantial number of small manufacturers of goods falling under the residuary item 68 of the Central Excise Tariff. Hon'ble Members will recall that the quantum of duty-free clearances was reduced from Rs. 30 lakhs to Rs. 15 lakhs. I had opposed this change then. As a measure of undoing the hardship caused to such small manufacturers, I propose to provide for complete exemption from duty for clearances upto Rs. 30 lakhs per annum. In other words, small manufacturers of goods falling under item 68 of the Central Excise Tariff, whose capital investment on plant and machinery does not exceed Rs. 10 lakhs, will be eligible for complete exemption from duty on their first clearances of goods upto Rs. 30 lakhs in a financial year provided their clearances during the preceding financial year did not exceed Rs. 30 lakhs. For the remaining part of the current financial year, the quantum of clearances eligible for full exemption from duty will be fixed at a correspondingly lower figure. This concession is expected to cost Rs. 2.4 crores in a full year.

102. Paper and allied products are in short supply in the country and new investment in this sector has not been readily forthcoming. Much can be done by smaller units to help in filling the production gap. To encourage them, I propose to extend a concessional rate of duty of 20 per cent ad valorem as against the present rate of 30 per cent, to paper and paper board produced by small manufacturers whose clearances in the preceding financial year did not exceed 300 tonnes of paper and paper board. This concession will cost a little less than Rs. 1 crore in a full year.

103. The electronics industry has considerable employment and export potential. We have the necessary skills and expertise and these should be harnessed through appropriate fiscal incentives for development of the electronics industry in a big way. This is a field which offers great scope to small scale manufacturers. I am, therefore, proposing some duty concessions in respect of the industry. There will be a reduction in customs duty on specified items of capital goods such as machines and instruments required by the electronics industry and not produced within the country. The customs duty on such items will be reduced from the present levels of duty (which in some cases are as high as 89 per cent ad valorem) to a total of 25 per cent ad valorem. Similarly, I also propose to reduce the customs duty on specified raw materials and components required for the electronics industry from their present levels (which in some cases are higher than 200 per cent ad valorem) to 45 per cent ad valorem plus countervailing duty where an excise duty is leviable under item 68. These two concessions will cost the exchequer Rs. 4.7 crores in a full year.

104. The experience of other countries shows that the growth of consumer electronics facilitates in due course the development of other sophisticated lines of production in electronics. Television is a powerful medium of communication and education. With a view to enabling a larger number of people to get the benefit of this medium, I propose to reduce the excise duty on cheaper priced T.V. sets from 15 per cent to 10 per cent ad valorem, and to effect a corresponding reduction in the duty on other T.V. sets from 30 per cent to 25 per cent ad valorem. These concessions would entail a revenue sacrifice of Rs. 1.5 crores in a year.

105. Radio is an equally powerful instrument of education and entertainment and is more widely in use. Government considers that single and two band radio sets should be popularised particularly in rural areas. The licence fee on such sets has proved to be irksome and inhibits purchase of radio sets by the rural folk. It is, therefore, proposed to abolish the fee in respect of single and two band radio sets including transistor sets. This measure, which I am sure will be widely welcomed, will cost Government about Rs. 4 crores.

106. Our computer industry is still in its infancy, compared with those of other countries. In order to provide an additional incentive for indigenous production and improvement, I propose to reduce the excise duty on indigenously manufactured computers from 25 per cent to 20 per cent ad valorem.

107. Ship building is a high priority industry and has an important part to play in promoting economic self reliance. The Indian ship building industry is finding it increasingly difficult to face competition from foreign shipyards. I, therefore, propose to extend full exemption from excise duty to ocean going vessels built in Indian shipyards. This relief would cost about Rs. 5 crores in the current financial year.

108. Hon'ble Members would be aware that Government has been following the practice of bringing down the import duty on selected machinery items having no indigenous angle to 25 per cent ad valorem as a measure of reducing capital costs in industries. Carrying this process further, I propose, this year, to reduce the import duty to 25 per cent ad valorem on twelve more items of capital equipment. These include five items of machinery used in the printing industry, such as High speed Letter press rotary and off-set rotary printing machines, Mono/Lino Type Casting machines etc. These concessions would entail a revenue sacrifice of Rs. 1.84 crores in a full year.

109. The cost of high pressure gas cylinders constitutes a significant portion of the total capital outlay required by the Gas Industry. With a view to reducing, at least in part, this capital outlay, I propose to extend complete exemption from customs duty on steel tubes imported for fabrication of high pressure gas cylinders. I also propose to reduce the excise duty on such cylinders from the existing level of 15 per cent, to 8 per cent ad valorem, which is the duty level applicable under Item 68. These two measures, taken together, are estimated to cost Rs. 1.89 crores in a full year.

110. I have a proposal of general application, which is intended to facilitate manufacturers of excisable goods using inputs on which excise duty is leviable. In order to give relief in such cases, two procedures are in vogue at present. One is what is called the set-off procedure. The other is the proforma credit procedure under rule 56A of the Central Excise Rules. The proforma credit procedure is generally recognised to be more beneficial and less irksome to the manufacturers. I, therefore, propose to replace the existing concessions based on the set-off procedure by similar concessions based on the proforma credit procedure. I am sure that this measure will be welcomed by the industry.

111. It is a little painful for me to remind Hon'ble Members that last year's budget had increased excise duty on a number of articles of common consumption to a significant extent. I propose to reverse this trend. Thus —

- Specified life-saving drugs, 30 in number, will be fully exempted from excise duty. The list will be kept under periodical review with a view to adding more items as may be warranted;
- Controlled cloth is meant for the weaker sections of society and its cost should be as low as possible. I, therefore, propose to exempt controlled cloth from excise duty.
- Cotton and Cotton-viscose blend hosiery consisting of items like banians are of relatively low value and these are now subject to excise duty at 8 per cent. I propose to exempt them fully from excise duty.
- Cycles are the poor man's conveyance. I therefore, propose to totally exempt cycles and cycle parts falling under Item 68 from excise duty.

- Sewing machines, which are indispensable to the housewife and also enable the weaker sections to earn a living, will also be fully exempted from excise duty.
- Pressure cookers which take the drudgery out of the house wife's daily tasks and save fuel now attract duty at 15 per cent. I propose to reduce it to 10 per cent.

112. I also propose to make substantial reductions in excise duty on some other items of everyday use. Accordingly —

- Excise duty on cheaper varieties of toilet soap will be reduced from 10 per cent to 5 per cent;
- Excise duty on tooth paste will be reduced from 20 per cent to 10 per cent;
- Vacuum and gas-filled bulbs, not exceeding 60 watts will have the duty reduced from 15 per cent to 10 per cent.

113. I am sure these substantial concessions, which would cost the exchequer approximately Rs. 15 crores in a full year, will be welcomed by Parliament and by the public. I also hope that industry and trade will play fair by the consumer and pass on the benefit of these only reductions to the consumer.

114. Our Party's election manifesto has referred to the need to encourage dieselisation of taxis. In fulfilment of this commitment and with a view to giving an incentive for taxi-owners to go in for dieselisation, I propose to extend full excise duty exemption to diesel engines used for conversion of petrol driven taxis.

115. My second proposal is aimed at giving relief to the cycle rickshaw driver. Powered cycle rickshaws are already exempt from excise duty. To encourage motorisation of non-powered cycle rickshaws, I propose to extend full duty exemption for internal Combustion engines used for this purpose. I am sure Hon'ble Members will welcome this measure, as a visible sign of our keenness to reduce physical strain and at the same time encourage this relatively cheap means of transport.

116. Before I leave the field of indirect taxes, I have a major decision of policy to announce. For the past couple of decades, there has been a persistent public demand for the setting up of an independent Appellate Tribunal for customs and central excise matters, somewhat similar to the set-up on the Direct Taxes side. This demand has recently been endorsed by the Estimates Committee of Parliament. Government has, in the past not been in favour of such a system, as it was felt that it would not be appropriate in the case of indirect taxes, and that the present departmental machinery was in fact adopting an objective approach. I think a time has come when we should gracefully accept the common view, which is based on the dictum that justice should not only be done but should also seem to be done. It is in this spirit that provision has been made in the Finance Bill for setting up an Appellate Tribunal to hear appeals in respect of customs, central excise and gold control matters. This Tribunal will be independent of the executive machinery charged with the responsibility of day-to-day administration of revenue laws. I have no doubt that this measure will meet with the whole-hearted approval of Parliament and of trade and industry.

117. My taxation proposals will yield a sum of Rs. 223.22 crores in a full year in central excise duties and Rs. 39.58 crores in customs duties. The reliefs I have announced add up to Rs. 34.75 crores on the central excise side and Rs. 7.93 crores on the customs side. The net yield is, therefore, Rs. 188.47 crores from central excise duties and Rs. 31.65 crores from customs duties. The accrual to the Central exchequer in a full year will be Rs. 144.85 crores and the share of the States will be Rs. 75.27 crores.

118. Where changes are proposed to be made by notifications, effective from the 19th June, 1980, copies of such notifications will be laid on the Table of the House in due course.

119. I wish to say now a few words on behalf of my honourable colleague, the Minister of Communications, Payment of dearness allowance and sanction of bonus linked to

productivity to the staff of the Posts and Telegraphs Department have increased the working expenses of the Department. It has therefore, become necessary to increase the tariffs on a few selected services. In making tariff revision proposals, Government has carefully avoided revision of charges for such services as are generally used by the common man. There will be no increase in the price of post cards and inland letters. The tariff for letters is, however, being increased from 30 paise to 35 paise at the lowest slab. The rate for parcels will be stepped up from Rs. 1.50 to Rs. 2.00 for every 500 grams. The charges for installation and shifting of telephone connections are also being increased. Local calls beyond 5,000 calls in a quarter will be charged at 50 paise per call as against 40 paise at present. A memorandum showing the proposed tariffs is being circulated along with Budget papers. It will be seen that the charges for the bulk of postal and tele-communications services have been left untouched. The changes would take effect from a date to be notified after the Finance Bill is passed by Parliament. The proposed tariff revisions are estimated to bring in an additional revenue of Rs. 27.10 crores per annum. The additional revenue during the year 1980-81 would be of the order of Rs. 13 crores and has been taken into account in estimating the revenues of the Posts and Telegraphs.

120. The tax effort net of reliefs proposed in the Budget will on the whole bring in about Rs. 282 crores for the current year, of which Rs. 223 crores will accrue to the Centre. There will be a residual deficit of Rs. 1417 crores which I propose to leave uncovered. This deficit is only a little over half the deficit of last year. It is my judgement that a deficit of this order will not have a significantly adverse impact on the economy. If the monsoon turns out to be normal and if we continue the sound economic policies already initiated, there is every hope that there will be an appreciable improvement in agriculture and industrial production resulting in a

significant growth of GNP. We shall also pursue a responsible monetary policy so that expansion of bank credit for unproductive or speculative purposes is held in check.

121. Sir, within the constraints imposed by the difficult economic situation inherited by the present Government, I have endeavoured my best to provide relief to those who deserve it most. But since reliefs can only be palliatives and the real need of a poor society is growth, I have tried to impart a judicious stimulus to investment. With the higher levels of investment, in the public sector as well as the private sector, and its particular sectoral distribution, both production and employment should register a substantial increase. This Government has a special responsibility towards the weaker sections of society who have so enthusiastically supported it. The Budget seeks to protect them through special programmes designed to promote their well being. It is also our firm resolve that no matter how difficult the economic situation is, the minimum basic needs of consumption of the poorer sections and the middle classes will be met through a reinvigorated public distribution system. With a strong and cohesive Government it should be possible to utilise fully the existing production potential.

122. My Budget represents a modest contribution to the process of restoring the country's economy to the path of stability, growth and social justice. Its success, however, depends upon the cooperation of all people who work in the fields or factories, power stations or ports, railways or coal mines. The people of this country have high hopes about the ability of the Present Government to achieve these goals and I am sure will be prepared to give their whole hearted support in this task. It should be the common endeavour of all of us, rising above partisan prejudices and passions to harness the people's enthusiasm for the tasks of development.

A. C. TIWARI, Jt. Secy.

